Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-23
01-15 दिसंबर, 2023 (पाक्षिक)
₹20

'भाजपा को सेवा का अवसर दें'

"जन-जन की यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार"

उदयपुर (राजस्थान) में 20 नवंबर, 2023 को एक विशाल रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

चीचली में 14 नवंबर, 2023 को एक विशाल जनसभा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते मध्य प्रदेश भाजपा नेतागण

धोद में 21 नवंबर, 2023 को एक जनसभा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को हल सौंपकर उनका स्वागत करते राजस्थान भाजपा के नेतागण

नवलगढ़ (राजस्थान) में 21 नवंबर, 2023 को जनसभा में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

जबलपुर (मध्य प्रदेश) में 19 नवंबर, 2023 को एक रैली के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

सिवनी मालवा में 14 नवंबर, 2023 को एक विशाल चुनावी रैली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते मध्य प्रदेश भाजपा नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **आदिवासी योद्धाओं ने देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया: नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस, 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' और प्रधानमंत्री विशेष कमजोर...

09 लोगों ने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है : नरेन्द्र मोदी

राजस्थान के पाली में 20 नवंबर, 2023 को...

12 'राज्य में भाजपा सरकार का रहना बहुत जरूरी है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में जनसभाओं को संबोधित...

14 'राज्य में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में जनसभाओं को संबोधित किया। अपने...

31 जहां जवान तैनात हैं, वह जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 नवंबर को दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के...

श्रद्धांजलि

राष्ट्र निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर 26

लेख

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका / एस. जयशंकर 28

राष्ट्र-निर्माण का जनजातीय पथ / अर्जुन मुंडा 29

अन्य

'तेलंगाना सरकार ने मादिगा समुदाय के साथ ही हर किसी से विश्वासघात किया है' 15

जनता कांग्रेस की बेईमान सरकार को घर बैठाए और भाजपा को सेवा का अवसर दे : जगत प्रकाश नड्डा 16

'नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा भारत का कद' 17

भाजपा अपने संकल्प पत्र का अक्षरशः कार्यान्वयन करती रही है और आगे भी किये गए सभी वादे पूरा करेगी: जगत प्रकाश नड्डा 19

'भाजपा संकल्प पत्र विकास का रोडमैप है' 20

भाजपा हर वर्ष 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के तौर पर मनाएगी: अमित शाह 21

'मंडल सशक्तीकरण अभियान' का शुभारंभ 22

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9 नवंबर, 2023 तक 17.59 प्रतिशत बढ़कर 12.37 लाख करोड़ रुपये रहा 23

मोदी स्टोरी 25

कमल पुष्प 27

आपातकाल के सेनानी नरेन्द्र मोदी 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

कांग्रेस ने गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवारों को हमेशा वंचित रखा, वहीं भाजपा सरकार ने उन्हें सदैव वरीयता दी है।

(18 नवंबर, 2023)

जगत प्रकाश नड्डा

जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला, लूट और छलावा होगा और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास, महिलाओं का स्वावलंबन और स्थिरता होगी।

(17 नवंबर, 2023)

अमित शाह

अशोक गहलोत ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महिलाओं पर अत्याचार और पेपर लीक के मामलों में नंबर-1 बना दिया है।

(17 नवंबर, 2023)

राजनाथ सिंह

मध्य प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों (जावरा, सिवनी मालवा और हरदा) में आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग दो दशक के शासनकाल में मध्य प्रदेश को बीमारु राज्य की श्रेणी से निकालकर तेज़ी से विकसित होते राज्यों की क़तार में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार भी जनता भाजपा के पक्ष में ही जनादेश देने जा रही है।

(14 नवंबर, 2023)

बी.एल. संतोष

जिस तरह से आपकी पूर्व पार्टी कांग्रेस ने गुजरात के विकास को धीमा करने के लिए कई वर्षों तक गुजरात के राजभवन का उपयोग किया और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मात देने की कोशिश की, उसे भुलाया नहीं गया है सर। जनता की यादें हमेशा ताजा रहती हैं।

(21 नवंबर, 2023)

निर्मला सीतारमण

हम 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने' के अपने सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर। यही कारण है कि भारत की समुद्री नीति पूरी तरह से अपने संक्षिप्त नाम 'सागर' में समाहित है, जो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करती है।

(15 नवंबर, 2023)

कमल संदेश परिवार की ओर से
लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि (15 दिसंबर) पर
शत-शत नमन!
(31 अक्टूबर, 1875—15 दिसंबर, 1950)

संपादकीय

राष्ट्र के विकास एवं अंत्योदय के प्रति संकल्पित भाजपा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रांची, झारखंड में 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर अपने संबोधन में उन सभी जनजातीय योद्धाओं का स्मरण किया, जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। विदेशी दासता से मुक्ति के लिए चले स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय योद्धाओं की वीरता आज भी पूरे राष्ट्र को प्रेरित करती है तथा उनकी समृद्ध विरासत देश के युवाओं को दिशा दिखा रही है। देश के हर भाग में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध अपने रक्त एवं पसीने से प्रेरणादायी संघर्ष किया है। उनका संघर्ष देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। देश के इन जनजातीय राष्ट्रीय नायकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता एवं सम्मान व्यक्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाने का आह्वान किया है।

जहां मध्य प्रदेश में 77 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में मतदान के दूसरे चरण में 75 प्रतिशत से अधिक मत डाले गए हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य को 'बीमारू राज्यों' की श्रेणी से बाहर निकालकर व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। परिणाम यह है कि आज देश में तेजी से विकास कर रहे राज्यों में मध्य प्रदेश को गिना जाता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा मध्य प्रदेश के लिए जारी 'दृष्टि पत्र' में किसान, मजदूर, युवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वंचित समुदायों के लिए कई योजनाओं के माध्यम से राज्य के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा रखी है। जहां प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य में किसानों की समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं, वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को अपनी उपज का लाभदायक मूल्य प्राप्त होगा। हर संभाग में आईआईटी एवं आईआईएम जैसे प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के खुलने से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसरों का निर्माण होगा। 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना', 450 रुपए में उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलिंडर, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की महिलाओं को स्नातकोत्तर निःशुल्क शिक्षा', लाडली लक्ष्मी एवं लखपति दीदी योजना, अटल मेडिसिटी, हर जनजातीय जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय तथा जबलपुर एवं ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जैसे अनेक जनकल्याणकारी कदम से निश्चित ही मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा राजस्थान के लिए जारी 'दृष्टि पत्र' महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा एवं किसानों की नीलाम हुई भूमि की उचित मुआवजा सुनिश्चित करता है। जहां 'मातृ वंदन' योजना की राशि को 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा, वहीं उज्ज्वला लाभार्थी महिलाओं को मात्र 450 रुपए में गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा। यह 'दृष्टि पत्र' राजस्थान के हर संभाग में आईआईटी एवं आईआईएम की तर्ज पर प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालय खोलकर नई पीढ़ी के लिए अनेक नए अवसरों का सृजन करेगा। 'लाडली प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत मेधावी युवतियों को 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर स्कूटी देने का भी प्रावधान किया गया है। आज जब राजस्थान को एक नारी विरोधी कुशासन वाली कांग्रेस सरकार से संघर्ष करना पड़ रहा है, भाजपा हर जिले में महिला पुलिस चौकी, हर पुलिस चौकी में महिला डेस्क तथा एंटी-रोमियो स्क्वॉड गठितकर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

महिला, अनु.जाति, अनु. जनजाति, समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं के साथ भाजपा जनता को भ्रष्टाचार-मुक्त शासन देने के लिए कृतसंकल्पित है

तेलंगाना के लिए भाजपा 'दृष्टि पत्र' केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया। इस दृष्टि पत्र में राज्य में हर वर्ष 17 सितंबर को 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' तथा हर वर्ष 27 अगस्त को 'रजाकार विभीषिका स्मृति दिवस' मनाने का संकल्प है। राज्य में महिला, अनु. जाति, अनु.जनजाति, समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं के साथ भाजपा जनता को एक भ्रष्टाचार-मुक्त शासन देने के लिए कृतसंकल्पित है। आज हर राज्य में भाजपा ने एक ऐसे जनांदोलन का रूप ले लिया है जो न केवल 'अंत्योदय' के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर समाज में गरीब से गरीब, अंतिम पायदान के व्यक्ति की सेवा करते हुए विकसित भारत के निर्माण को समर्पित है। राष्ट्र के लिए अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए जनता आज भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दे रही है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह, खूंटी, झारखंड

आदिवासी योद्धाओं ने देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को पूर्णता प्रदान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। योजनाओं की संतृप्ति के इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़े कदम में श्री मोदी ने 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शुरू की।

यात्रा का लक्ष्य लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगा। यात्रा के दौरान तैयार किए गए विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस, 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' और प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने पीएम-किसान की 15वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने झारखंड में रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्रों में 7200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का एक वीडियो संदेश चलाया गया तथा श्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव के साथ-साथ रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क-सह-स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की अपनी यात्रा को याद करते हुए की। उन्होंने दो साल पहले आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करने का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रत्येक नागरिक को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं और इसके गठन में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डाला।

स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योद्धाओं का महत्वपूर्ण योगदान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आदिवासी गौरव के लिए भगवान बिरसा मुंडा के प्रेरक संघर्ष का जिक्र करते हुए असंख्य आदिवासी नायकों के साथ झारखंड की भूमि के जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तिलका मांझी, सिधू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर, पीतांबर, जतरा टाना भगत और अलबर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि आदिवासी योद्धाओं ने देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और मानगढ़ धाम के गोविंद गुरु, मध्य प्रदेश के तांत्या भील, छत्तीसगढ़ के भीमा नायक, शहीद वीर नारायण सिंह, मणिपुर के वीर गुंडाधुर, रानी गाइदिनल्यू, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेश

की रानी दुर्गावती के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने ऐसी शख्सियतों की उपेक्षा पर दुःख जताते हुए अमृत महोत्सव के दौरान इन नायकों को याद करने पर संतोष व्यक्त किया।

विकसित भारत के चार 'अमृत स्तंभ'

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज झारखंड से दो ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हो रही है। पहली विकसित भारत संकल्प यात्रा जो सरकार और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की पूर्णता के लक्ष्यों का एक माध्यम होगी जो विलुप्त होने वाली जनजातियों की रक्षा करेगी और उनका पोषण करेगी।

श्री मोदी ने विकसित भारत के चार 'अमृत स्तंभ' या विकसित भारत के स्तंभों अर्थात् महिला शक्ति या नारी शक्ति, भारत के खाद्य उत्पादकों, देश के युवाओं और अंत में भारत के नव-मध्यम वर्ग और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में विकास की डिग्री विकास के इन स्तंभों को मजबूत करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्तमान सरकार के पिछले 9 वर्षों में चार स्तंभों को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास और कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

श्री मोदी ने 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले गांवों में स्वच्छता का दायरा महज 40 प्रतिशत था, जबकि आज देश पूर्णता का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 2014 के बाद की अन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एलपीजी कनेक्शन 50-55 प्रतिशत गांवों से बढ़कर आज लगभग 100 प्रतिशत हो गया है, 55 प्रतिशत से 100 प्रतिशत बच्चों को जीवनरक्षक टीके लगाए जा रहे हैं, आज़ादी के कई दशकों के बाद नल के पानी के कनेक्शन 70 प्रतिशत परिवारों में दिए गए जो लगभग एक दशक पहले महज 17 प्रतिशत था। उन्होंने कहा, "मोदी ने वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाई है।"

श्री मोदी ने 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले गांवों में स्वच्छता का दायरा महज 40 प्रतिशत था, जबकि आज देश पूर्णता का लक्ष्य लेकर चल रहा है

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने आसान परिणामों की ओर जाने के प्रलोभन का विरोध किया है और लंबे समय से लंबित मुद्दों पर ध्यान दिया है। उन्होंने 18,000 गांवों के विद्युतीकरण का उदाहरण दिया जो अंधकार युग में रहने के लिए अभिशप्त थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-यापन में आसानी के प्रमुख मापदंडों को 110 जिलों में उठाया गया, जिन्हें पिछड़ा घोषित किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने इन जिलों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। श्री मोदी ने बताया कि इन जिलों में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है। उन्होंने कहा, "आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के माध्यम से विस्तारित किया जा रहा है।"

विकसित भारत संकल्प यात्रा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी आती है जब देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं।" उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है, जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के पीछे यही भावना है, जो आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से शुरू होकर अगले वर्ष 26 जनवरी तक चलेगी।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के हर गांव में जाएगी और हर गरीब और वंचित व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाएगी।"

पीएम जनमन

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार पीएम जनमन या पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। उन्होंने कहा कि यह अटलजी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया और एक अलग बजट आवंटित किया। श्री मोदी ने बताया कि आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ाया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी भी जंगलों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाखों की आबादी वाले 75 ऐसे आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों की पहचान की है जो देश के 22 हजार से अधिक गांवों में रहते हैं। श्री मोदी ने कहा, "पहले की सरकारें आंकड़ों को जोड़ने का काम करती थीं, लेकिन मैं आंकड़ों को नहीं, जिंदगियों को जोड़ना चाहता हूं। इस लक्ष्य के साथ पीएम जनमन आज शुरू हो गया है।" उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस महाअभियान पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।

पीएम-किसान की 15वीं किस्त जारी

किसानों के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कदम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लगभग 18,000 करोड़ रुपये की 15वीं किस्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी की गई। योजना के तहत अब तक 14 किश्तों में किसानों के खातों में 2.62 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क-सह-स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया

पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के बारे में चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब तक 2,75,000 करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं। उन्होंने पशुपालकों और मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, पशुओं के मुफ्त टीकाकरण पर 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य सम्पदा योजना के तहत वित्तीय सहायता और देश में 10 हजार नए किसान उत्पादन संघों के गठन के बारे में भी बताया। बाजार को अधिक सुलभ बनाकर किसानों के लिए लागत में कमी लायी जा रही है।

संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि अमृत काल के चार अमृत स्तंभ यानी भारत की महिला शक्ति, युवा शक्ति, कृषक शक्ति और हमारे गरीब और मध्यम वर्ग की शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे।

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा झारखंड के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे।

पीएम पीवीटीजी मिशन

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी तरह की पहली पहल— 'प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह (पीएम पीवीटीजी) विकास मिशन' भी लॉन्च की। देश के 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी 22,544 गांवों (220 जिलों) में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 28 लाख है।

ये जनजातियां बिखरी हुई सुदूर और दुर्गम बस्तियों में रहती हैं, अक्सर वन क्षेत्रों में और इसलिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाले एक मिशन में पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा पीएमजेएवाई, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, शत-प्रतिशत टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण, पीएम जनधन योजना आदि के लिए अलग से पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्य बातें

- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई क्षेत्रों में लगभग 7200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया।
- प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनमें एनएच 133 के महगामा-हंसडीहा खंड के 52 किमी लंबे हिस्से को चार लेन का बनाना, एनएच 114 ए के बासुकीनाथ-देवघर खंड के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को चार लेन का बनाना; केडीएच-पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट; आईआईआईटी रांची का नया शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन शामिल है।
- जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया, उनमें आईआईएम रांची का नया परिसर, आईआईटी आईएसएम धनबाद का नया छात्रावास; बोकारो में पेट्रोलियम तेल और स्नेहक (पीओएल) डिपो; कई रेलवे परियोजनाएं जैसे हटिया-पकरा खंड, तलगरिया-बोकारो खंड और जारंगडीह-पतरातू खंड का दोहरीकरण शामिल है। इसके अलावा, झारखंड राज्य में शत-प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण की उपलब्धि भी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई।
- भारत में विकास की डिग्री अमृत काल के चार स्तंभों— महिला शक्ति, युवा शक्ति, कृषक शक्ति और हमारे गरीब और मध्यम वर्ग की शक्ति को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
- मोदी ने वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाई है।
- मैं भगवान बिरसा मुंडा की इस भूमि पर वंचितों का कर्ज चुकाने आया हूं।
- सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी आती है, जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सभी संभावनाएं खत्म हो जाएं।
- 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से शुरू होकर अगले वर्ष 26 जनवरी तक चलेगी। ■

विधानसभा चुनाव प्रचार

पाली और पीलीबंगा (राजस्थान)

लोगों ने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है : नरेन्द्र मोदी

गत 17 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 70 के लिए मतदान संपन्न हुए। मध्य प्रदेश में 77.15 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 75.88 प्रतिशत मतदान हुए। अब बाकी राज्यों—राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव क्रमशः 25 नवंबर और 30 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 03 दिसंबर, 2023 को होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेतागण इन राज्यों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान कर रहे हैं—

राजस्थान के पाली में 20 नवंबर, 2023 को हुई जनसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर राज्य में भाजपा सरकार की वापसी की घोषणा की। उन्होंने कहा, "पूरा राजस्थान आज एक सुर में कह रहा है—जन-जन की है यही पुकार...आ रही है भाजपा सरकार।" देश के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा देश, विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। इसलिए यहां ऐसी सरकार जरूरी है, जो राज्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

सभा स्थल पर भारी संख्या में उमड़े समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच श्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा, "दुर्भाग्य से पिछले पांच साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने आप लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया है।" उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही सब कुछ है। ये तुष्टीकरण के अलावा कुछ सोच नहीं सकती।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है... राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर आंखों पर पट्टी बांध लेती है। राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग कांग्रेस के असली चेहरे को पहचान गए हैं। महिला विरोधी कांग्रेस, कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर वन बना दिया। उन्होंने कहा, "यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहनों-बेटियों ने जो शिकायतें की हैं, वो फर्जी हैं। मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर उचित ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। इसलिए, कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता महिला विरोधी है।"

श्री मोदी की दूसरी रैली पीलीबंगा में हुई, यहां उन्होंने कहा कि श्रमवीरों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "जिसने गरीब को लूटा है, उसे जेल भेजने के लिए सारी तैयारी है।"

राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूटतंत्र है। श्री मोदी ने राजस्थान में सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया।

हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की सेहत को महत्व देती है और इस क्षेत्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का उपचार भी घर के करीब हो, भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार, विरासत और विकास; दोनों को महत्व देती है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। ■

तारानगर एवं झुंझुनू

राजस्थान में अपने प्रचार अभियान को और धार देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर, 2023 को चुरू और झुंझुनूं में दो जनसभाओं को संबोधित किया। चुरू में उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा, आप बीजेपी को चुनेंगे, तो हम इन सारे भ्रष्टाचारियों को आउट करेंगे। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत राजस्थान की ही होगी'।

राज्य की कानून व्यवस्था पर जोरदार निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं-दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया।

कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "नेक नीयत और कांग्रेस का वही रिश्ता है जो उजाले और अंधेरे का होता है। मुझे बताइए, जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए, उसकी नीयत कैसी होगी? राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद हर घर जल का अभियान और तेज होगा। राजस्थान में अटकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।"

उन्होंने राजस्थान के लोगों को ये भी भरोसा दिया कि मुफ्त राशन की योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा।

श्री मोदी ने झुंझुनूं में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित किया, लोगों की भारी भीड़ के बीच कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "राजस्थान का रुझान क्या है, ये तो खुद मुख्यमंत्री ने यहां कुछ दिन पहले बता दिया। एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों और विधायकों ने 5 साल कोई काम नहीं किया। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है—पापा की सरकार नहीं आएगी।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों को लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। उन्होंने कहा, "विकास, वहीं होता है जहां विश्वास होता है। जहां सुरक्षा होती है। जहां सम्मान सुरक्षित होता है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से ये सब कुछ छीना है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो, तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन-बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।"

उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना के 1 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार, राजस्थान के भी हैं। विश्वकर्मा योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे कुम्हार, लोहार, सुनार, सुत्तार, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे हस्तशिल्पियों की कांग्रेस ने कोई सुध नहीं ली। कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है।"

किसानों के हित की बात करते हुए श्री मोदी ने कहा, "पीएम किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6 हजार रुपए मिलते हैं। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने का फैसला किया है। यहां बीजेपी सरकार आएगी तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के 12 हजार रुपए मिला करेंगे।"

उन्होंने कहा कि आज देश को भाजपा पर भरोसा है। क्योंकि भाजपा जो कहती हैं, वो करके दिखाते हैं। वहीं कांग्रेस का मतलब है, झूठे वायदे, झूठी सौगंध और झूठा प्रचार।

जनसभा में 'कमल चुनेगा राजस्थान' की गूंज के बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है, इसलिए बूथ-बूथ पर कमल खिलाना जरूरी है। ■

भरतपुर एवं नागौर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 नवंबर, 2023 को भरतपुर और नागौर में जनसभाओं को संबोधित किया। भरतपुर में अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत कई उपलब्धियों के साथ दुनिया में अग्रणी बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान को कांग्रेस भ्रष्टाचार, दंगा और अपराध में अग्रणी बना दिया है। कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान-माल की सुरक्षा करे। लेकिन बीते 5 वर्षों में बहनों-बेटियों और दलितों-वंचितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। यहां के लोग होली, रामनवमी, हनुमान जयंती कोई भी त्योहार शांति से नहीं मना पाए। दंगे-पत्थरबाजी और कर्फ्यू राजस्थान में यही सब चलता रहा। क्योंकि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब-कुछ है। इसके लिए कांग्रेस को जनता-जनार्दन का जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, तभी तो आज राजस्थान की जनता उन्हें कह रही है—3 दिसंबर, कांग्रेस छू-मंतर!

महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार की लापरवाही पर श्री मोदी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री खुद कहें कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती हैं, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये

कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री और मंत्री को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है? ये बयान राजस्थान की हर माता-बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय ईनाम में टिकट दे दिया है।

दलितों के प्रति कांग्रेस की सोच पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी स्वभाव से ही दलित विरोधी है। कांग्रेस के शासन में दलितों के खिलाफ अत्याचार के नए-नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दलितों के प्रति कांग्रेस की सोच का सबसे ताजा उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया है। देश को हीरालाल सामरिया जी के रूप में पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला है। वे यहीं डीग के रहने वाले हैं। कांग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलित अधिकारी की नियुक्ति भी पसंद नहीं आई। दरअसल, कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती। कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर से लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू तक यही किया है। जबकि भाजपा बाबा साहेब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है।

श्री मोदी ने ने दोपहर बाद नागौर में दूसरी सभा में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने पांच साल में विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने यहां कुशासन, भ्रष्टाचार और घोटालों वाली सरकार दी है। उन्होंने कहा कि खुद यहां के मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो यहां अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। उन्होंने कहा कि इनका दिल्ली-दरबार, अपने ही सीएम की कुर्सी को लूटने में बिजी रहा और सीएम उनसे निपटने में बिजी रहे। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। इसीलिए अब जनता कह रही है—"गहलोत जी! कोनी मिलै वोट जी!" ■

बायतु

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर, 2023 को बाड़मेर जिले के बायतु में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को फर्जी बता दें और महिला अत्याचार पर मंत्री विधानसभा में कहे कि यह मर्दों का प्रदेश है तो अत्याचारियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के चलते ही वो जहां भी सत्ता में आती है, वहां आतंकियों और दंगाइयों के हौसले बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में आतंकवाद समर्थक नारे लग रहे हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अब तो कांग्रेस के काले कारनामोंवाली लाल डायरी भी बढ़-चढ़कर बोलने लगी है। श्री मोदी ने कहा कमल का बटन ऐसे दबाइए, जैसे भ्रष्टाचारियों को फांसी दे रहे हों।

राजस्थान में परीक्षाओं में पेपर लीक का जिक्र करते हुए श्री

मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के नौजवानों को पूरी तरह से पेपरलीक माफिया के हवाले छोड़ दिया। राजस्थान में परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो...ये असंभव सा हो गया है। पेपरलीक माफिया के तार सीधे-सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी की ही चर्चाएं थीं। अब काली कमाई वाले लॉकरों की भी चर्चा होने लगी है। यहां राजस्थान में लॉकर से रुपयों का ढेर और कई किलो सोना निकला है। यह सोना कोई 'आलू वाला' नहीं, बल्कि असली सोना है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है, तो सीएम गहलोत मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दें...भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। राजस्थान के वीरों और वीरांगनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान से कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस जब केंद्र में थी, तो डर-डर कर सरकार चलाती थी। आतंकी हमले के बाद विदेश से मदद की गुहार लगाती थी। आज भाजपा सरकार में आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन के समापन पर कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर,जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में हाइवे का शानदार जाल भी बिछाया है। इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त करने के लिए हम हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार मोदी के हर काम को, हर कदम को रोकने में जुटी हुई है। आप जब वोट डालने जाएं तो, याद रखना कि कांग्रेस की सरकार ने गौमाता को भी लंपी की बीमारी के दौरान कष्ट में छोड़ा था। ये मोदी ही है, जो पूरे देश में पशुधन को मुफ्त टीकाकरण का अभियान चला रहा है। यह भी याद रखना है कि ये चुनाव सिर्फ विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था की वापसी के लिए है। प्रदेश के हर मतदाता को कांग्रेस को हटाने के लक्ष्य को याद रखना है। ■

बैतूल, शाजापुर एवं झाबुआ (मध्य प्रदेश)

'राज्य में भाजपा सरकार का रहना बहुत जरूरी है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के कई लोग तो घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने उनके झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं।" श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। दुनिया के एक्सपर्ट्स को ये भरोसा है कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएंगे और मैंने इसकी गारंटी भी मध्य प्रदेश सहित मेरे सभी परिवारजनों को दी है।

देश के गरीब और आदिवासियों के कल्याण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "ये भाजपा सरकार ही है, जो देशभर में आदिवासी सेनानियों और आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। कुछ दिन पहले जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गोंड संस्कृति को प्रदर्शित करनेवाले भव्य स्मारक का शिलान्यास हुआ है। जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24 हजार करोड़ रुपए की एक योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए भाजपा सबसे आगे बढ़कर काम करती है। मेरे गरीब भाई-बहनों की चिंता को समझते हुए हमने मुफ्त राशन की योजना लागू की, मेरा निश्चय है इसे पांच साल और बढ़ा दिया जाएगा।"

बैतूल के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बैतूल के गुड़ को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' प्रोग्राम के तहत बढ़ावा दे रही है। यहां वुडन क्लस्टर और फर्नीचर क्लस्टर भी विकसित किया जा रहा है। इससे सैकड़ों छोटे-छोटे उद्योग विकसित होंगे और हजारों नए रोजगार यहीं पर सृजित होंगे।

शाजापुर में दूसरी जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया के विकसित से विकसित देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर से हर सेक्टर की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत आने के लिए आतुर हैं। निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि दुनिया का बहुत बड़ा मैनुफैक्चरिंग हब अब भारत बनने जा रहा है। शताब्दियों से दबी हुई भारत की ऊर्जा और इसकी शक्ति अब अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी जानते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है, जो जो हजारों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करती है और जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है। इसलिए, कांग्रेस आई...तबाही लाई...ये आपको हमेशा याद रखना है।

श्री मोदी ने झाबुआ में अपनी तीसरी जनसभा में कहा कि 2014 में मेरे परिवारजनों ने मुझे देश की जिम्मेदारी दी, तो मैंने संकल्प लिया- सबका साथ-सबका विकास। भाजपा ने सदैव वंचितों को वरीयता दी है। हमने जो समाज के आखिरी छोर पर छूटे हुए थे, हमने उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी परिवारों को हो रहा है। हमने निश्चय किया है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। अब तो एमपी भाजपा ने भी संकल्प लिया है कि दाल, तेल और चीनी पर भी रियायत कीमत पर मिलेगी।

बड़वानी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही आज देश में कोई भी इसकी बातों और वादों पर भरोसा नहीं कर रहा है। फिर भी कांग्रेस विधानसभा चुनावों में झूठे वादों का झुनझुना लेकर आ गई है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों और किसानों के नाम पर सिर्फ अपनी तिजोरी भरी है। उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं और युवाओं को सतर्क करते हुए कहा कि आजकल यहां एक नारा गूंज रहा है—कांग्रेस आई, तबाही लाई। बीते वर्षों के अनुभव से यह साफ हो गया है कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां-वहां संकट बहुत बढ़ गए हैं।

आदिवासियों के साथ अन्याय का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, सरकारें चलाई हैं, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने आदिवासियों का न तो विकास किया न ही उन्हें मान-सम्मान दिया। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर आदिवासियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ। भाजपा सरकार ने ही पहली बार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। सड़क, बिजली और पानी ये सुविधाएं, आदिवासी गांवों में अब भाजपा सरकार पहुंचा रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब आदिवासी मंत्रालय का बजट बहुत ही कम था। आज आदिवासी विकास के लिए बजट लगभग सवा लाख करोड़ रुपये का है। हमने एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या भी 5 गुना से अधिक बढ़ाई है। हमने लाखों आदिवासी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी बड़ी वृद्धि की है। भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार से मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवारों को डबल लाभ हुआ है। देशभर में हमने अपने सेवाकाल में आदिवासी परिवारों को 8 लाख से अधिक पट्टे दिए हैं।

जन कल्याणकारी योजनाओं पर उन्होंने कहा कि देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भूख से मौतों की खबरें सबसे अधिक आदिवासी क्षेत्रों से ही आती थी। हमने आदिवासी परिवारों की ये चिंता हमेशा-हमेशा के लिए दूर करने के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। अब हमने ये भी तय किया है कि इस योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। एमपी की भाजपा सरकार भी राशन आपके ग्राम योजना के तहत गांव-गांव राशन पहुंचाने में जुटी है। इतना ही नहीं सैकड़ों आदिवासी युवाओं को हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग भी देती है। उन्होंने कहा कि हमने शिल्पकार, राजमिस्त्री, बढ़ई, सुनार, दर्जी आदि कामगारों के लिए 13 हजार करोड़ रुपये की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है।

मध्य प्रदेश सहित देशभर के आदिवासियों से जुड़े कार्यों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान आदिवासी बच्चों का टीकाकरण बहुत कम होता था। आज मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का दायरा बहुत अधिक बढ़ा है। 'पीएम मातृवंदना योजना' के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के लिए सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार भी लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की लाखों बहनों को मदद दे रही है। आदिवासी परिवार की बहनों को भी विशेष सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार ही है, जिसने पहली बार सिकल सेल की बीमारी दूर करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। कांग्रेस तो सिर्फ 7-8 वन-उपजों पर ही समर्थन मूल्य देती थी। आज भाजपा सरकार 90 से अधिक वन उपजों पर एमएसपी देती है। ये भाजपा सरकार ही है जो वनधन योजना लेकर आई है। हजारों आदिवासी बहनें इस योजना की मदद से अपनी आय बढ़ा रही हैं। ■

संगठनात्मक नियुक्तियां

विजयेंद्र येदियुरप्पा बने कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 नवंबर, 2023 को विधायक श्री विजयेंद्र येदियुरप्पा को कर्नाटक प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ■

दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश भाजपा प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 नवंबर, 2023 को श्री पूर्णेश मोदी और श्री दुष्यंत पटेल को क्रमशः दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश भाजपा प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किया है।

मुंगेली एवं महासमुंद (छत्तीसगढ़)

'राज्य में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में जनसभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। उन्होंने कहा, "ये जयघोष है—पहला चरण, कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त।" उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, "मुंगेली के लोगों में भी उन्हें यही संकल्प चारों तरफ देख रहा है, हर तरफ एक ही गूंज है—3 दिसंबर को भाजपा आवत है।"

श्री मोदी ने पहली सभा मुंगेली में कहा कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने छत्तीसगढ़ के लोगों को पांच साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गरीब और पिछड़ों के साथ ही महिलाएं, नौजवान और किसान कांग्रेस की विदाई के लिए आतुर हैं।

छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप हैं। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को इसमें से कितना पैसा मिला? कांग्रेस के बाकी नेताओ के हिस्से में कितना माल आया और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना हिस्सा पहुंचा? एक-एक टिकट बेचकर कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं...इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए।" प्रधानमंत्री ने पीएससी घोटाले और शराबबंदी को लेकर भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा।

कांग्रेस के जिन नेताओं ने छत्तीसगढ़ के लोगों को पांच साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गरीब और पिछड़ों के साथ ही महिलाएं, नौजवान और किसान कांग्रेस की विदाई के लिए आतुर हैं

उन्होंने कहा, "एक तरफ कांग्रेस की झूठ की दुकान है तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। मोदी ने हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चावल और चने की गारंटी दी और पूरा किया। अब मोदी ने निश्चय किया है कि गरीबों को आने वाले 5 साल तक मुफ्त चावल-चना ऐसे ही मिलता रहेगा।"

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस सरकार ने हमें गरीबों के घर तेजी से नहीं बनाने दिए, लेकिन मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी।"

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो जन औषधि केंद्र खोल रही है, उसमें 100 रुपए की दवा, 20 रुपए तक मिलती है। उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ से ही मैंने गांव-गांव आधुनिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योजना शुरु की थी। जिस प्रकार ये गरीब परिवारों की सेवा कर रहे हैं, लोग इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर बुलाने लगे हैं।"

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को भाजपा की गारंटियों पर भरोसा होता है। राज्य में किसान कल्याण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किसानों को ज्यादा खरीद, ज्यादा दाम और साथ में बोनस की गारंटी दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तेंदुपत्ता संग्राहकों से जो छीना है, उसे भाजपा सरकार में जरूर वापस लौटाया जाएगा।" पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लूट-पाट, हत्या-छिनौती, हिंसा-दंगे और जमीन-कब्जे से मुक्ति की चाहिए। इसलिए भाजपा, शांत, अपराध मुक्त, दंगा मुक्त, आदिवासी अत्याचार मुक्त, छत्तीसगढ़ की गारंटी दे रही है।

श्री मोदी ने महासमुंद की दूसरी जनसभा में कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाई-बहनों का स्वास्थ्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार को कभी इनके स्वास्थ्य से भी कोई मतलब नहीं रहा है। बीते 5 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में और ओबीसी परिवारों में पोषण के अभाव में अनीमिया की स्थिति बदतर हुई है। हमने सिकल सेल अनीमिया से मुक्ति के लिए हाल में ही राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में हमारी आदिवासी बहनों-बेटियों की स्थिति बहुत खराब है। इसी स्थिति से बचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पोषण अभियान चला रही है। हम गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चना और चावल की सुविधा दे रहे हैं। गरीबों के हित को ध्यान में रखकर ही मुफ्त राशन योजना को अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि गर्भ के समय हर माता को 'मातृवंदना योजना' के तहत हज़ारों रुपए सीधे बैंक खाते में मिलें, ये काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ऐसी योजनाओं का पूरा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचने नहीं दे रही है। ■

सिकंदराबाद (तेलंगाना)

'तेलंगाना सरकार ने मादिगा समुदाय के साथ ही हर किसी से विश्वासघात किया है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 नवंबर, 2023 को तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना आज इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर है। दशकों के आंदोलन के बाद 10 साल पहले जो सरकार यहां बनी, वो तेलंगाना के गौरव और सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। इन सालों में तेलंगाना सरकार ने मादिगा समुदाय के साथ ही हर किसी से विश्वासघात किया है। जब आंदोलन के समय वादा किया गया था कि किसी दलित को ही तेलंगाना का पहला सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही राज्य बन गया, दलितों की आकांक्षाओं को कुचलकर केसीआर ने सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर लिया।

श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भी कांग्रेस और बीआरएस अलग नहीं हैं। भारत में राज्य, विकास योजनाओं के लिए दूसरे राज्यों के साथ Cooperation करते हैं, लेकिन बीआरएस की सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपये के शराब घोटाले को अंजाम दिया। ये लोग काम में नहीं, Corruption में Cooperation करते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने दलित बंधु स्कीम के तहत हजारों करोड़ रुपये देने की बात कही थी। लेकिन इसका लाभ किसे हुआ? सच्चाई ये है कि ये स्कीम बीआरएस विधायकों के रिश्तेदारों की स्कीम बन गई है। कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि दलित बंधु स्कीम के लाभार्थियों का चयन निष्पक्ष होना चाहिए। यहां की सरकार ने किसानों के लोन माफ करने का भी वादा किया था, लेकिन किसानों को इसका भी लाभ नहीं मिला। यहां की सरकार ने Irrigation Schemes के बदले आप लोगों को Irrigation Scams दिए हैं।

गरीबों और वंचितों के कल्याण पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा जिस मंत्र पर चलती है, वो सबका साथ, 'सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' है। हमारी सरकार सोशल जस्टिस-सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम तेलंगाना की धरती के महान सपूत गुर्रम जशुवा जी और उनके सामाजिक न्याय के कार्यों को अपनी प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री जातिवादी राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं। अभी हमने दो दिन पहले ही देखा है कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में एक वरिष्ठ दलित नेता और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का अपमान किया है, जो दलितों में भी अति दलित हैं। बहुत ही निर्लज्जता के साथ यह जताने की कोशिश की गई कि जीतन बाबू सीएम पद के योग्य नहीं थे।

बीआरएस और कांग्रेस की तुलना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना के मादिगा समुदाय को जितना बीआरएस से सतर्क रहना है उतना ही कांग्रेस से भी सावधान रहना है। बीआरएस तो दलित विरोधी है ही कांग्रेस भी उससे रत्ती भर कम नहीं है। बीआरएस ने नए संविधान की मांग करके बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है तो कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। ये कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहेब का पीठ पीछे विरोध करके उन्हें दो बार चुनाव नहीं जीतने दिया। कांग्रेस ने दशकों तक पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में न तो बाबा साहब की फोटो लगने दी और न ही उनको भारत रत्न दिया।

श्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे भाजपा भली-भांति समझती है और वह जल्द से जल्द इस अन्याय का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे, जो इस समुदाय के सशक्तीकरण का नया रास्ता बनाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया और संविधान ने जिस सामाजिक न्याय का दायित्व हमें दिया है, हम उसे हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। पूरी मजबूती के साथ हमारी सरकार मादिगा समुदाय के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। ■

सीकर एवं दौसा (राजस्थान)

जनता कांग्रेस की बेईमान सरकार को घर बैठाए और भाजपा को सेवा का अवसर दे : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 नवंबर, 2023 को राजस्थान के राउमावि (दांतारामगढ़, सीकर) और दौसा में आयोजित विशाल रैलियों को संबोधित किया तथा राजस्थान की जनता से भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण और कुशासन की राजनीति की प्रतीक कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंक भाजपा की विकास के प्रति समर्पित डबल इंजन वाली सरकार बनाने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव का उद्देश्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का है।

श्री नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने अपना सर्वस्व लुटानेवाले लोगों, योद्धाओं, देशभक्तों, संतों और समाज सुधारकों के राजस्थान को पिछले 5 साल में ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने जनता से अपील की कि 25 तारीख को भाजपा को जिताकर आपको ये ग्रहण हटाना है। भाजपा और कांग्रेस शासन के बीच का अंतर रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस होगी, वहां भ्रष्टाचार, घपले, महिला अत्याचार, व्यभिचार, लूट और घोटाले होंगे लेकिन जहां भाजपा होगी, वहां विकास, तरक्की, महिला सम्मान और युवाओं की आकांक्षाएं पूरे करने का रास्ता और गांव, गरीब, किसान का सशक्तीकरण होगा।

जहां कांग्रेस होगी, वहां भ्रष्टाचार, घपले, महिला अत्याचार, व्यभिचार, लूट और घोटाले होंगे लेकिन जहां भाजपा होगी, वहां विकास, तरक्की, महिला सम्मान और युवाओं की आकांक्षाएं पूरे करने का रास्ता और गांव, गरीब, किसान का सशक्तीकरण होगा

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, किसानों के साथ झूठ बोला गया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक हुए, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की गई और इतना ही नहीं इस भ्रष्ट गहलोत सरकार ने तो वृद्ध पेंशन में भी 450 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के भाई ने किसानों के सब्सिडी की खाद को एक्सपोर्ट कर दिया, अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने पिछले 5 साल में 11 हजार करोड़ रुपए का कान्ट्रैक्ट लिया। उन्होंने कहा कि अब 25 तारीख को इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार की राजस्थान से छुट्टी करने का समय आ गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संस्कार और शांति के लिए प्रसिद्ध राजस्थान, आज महिला उत्पीड़न और अपराध दर में नंबर 1 पर है। हाल ही में दौसा में एक पुलिसकर्मी ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। हर दिन राजस्थान में ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, महिलाओं पर तेजाब फेंका गया। महिला अत्याचार की बात करते हुए उन्होंने

जनता को चूरू, अलवर, प्रतापगढ़, बाड़मेर और भीलवाड़ा में हुई घटनाओं को याद दिलाया। अगर जनता चाहती है कि यह सब घटनाएं बंद हो जाए तो 25 नवंबर को गहलोत सरकार की राजस्थान से विदाई का इंतजाम करें।

उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने किसानों को वादा किया था कि उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेता अभी तक 10 दिन गिनते रहे लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ इसलिए 25 नवंबर को अशोक गहलोत की सरकार को हटाने का और कमल का फूल खिलाने का समय आ गया है। किसानों की कर्जमाफी तो दूर, उलटे राजस्थान के लगभग 19,400 किसानों की भूमि कुर्क हो गई। इसका लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने का समय या गया है और इसका तरीका केवल एक ही है कि जनता कांग्रेस की बेईमान सरकार को घर बैठाए और भाजपा को सेवा का अवसर दे।

श्री नड्डा ने राजस्थान में हुए घोटालों पर जनता को न्याय दिलाने की घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार आने पर कांग्रेस शासन में हुए मिड डे मील, पेपर लीक और वृद्धा पेंशन सभी घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी और दोषियों को जेल के पीछे डाला जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं-चावल अगले 5 वर्षों तक मुफ्त में दिए जाएंगे। 25 नवंबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की एक नई कहानी लिखनी है। ■

खेरवाड़ा और झाड़ोल, (राजस्थान)

कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य के साथ किया खिलवाड़: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक कराकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रक्षा मंत्री ने 22 नवंबर, 2023 को उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और झाड़ोल में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित सभाओं में यह बात कही।

श्री सिंह ने कहा कि राजस्थान में हालात इतने खराब हैं कि एक महिला विधायक खुद को असुरक्षित मानती हैं। उन्होंने कहा, ''अगर ऐसी स्थिति है तो मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है।''

महिलाओं पर अत्याचार

उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के शासन में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हुए है। उन्होंने कहा, ''ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए जो मां-बेटियों की रक्षा नहीं कर सकी।''

रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में राजस्थान में कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और जो पहले स्थापित हुए थे उन्हें बंद किया जा रहा है। "अशोक गहलोत सरकार ने विकास के लिए कुछ नहीं किया है और अगर कुछ किया है तो कुर्सी बचाने के लिए किया है। विकास करने के बजाय, वे आपस में लड़ रहे हैं।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के शासन के पांच साल "एक-दूसरे को मात देने में बीते" यह टिप्पणी क्रिकेट की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है, जहां दो टीमें मैच जीतने के लिए एक-दूसरे से लड़ती हैं।

इसके अलावा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री सिंह ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण जैसी विकसित परंपरा वाली पार्टी करार दिया।

श्री सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कुछ दवाओं पर 80 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर रही है। उन्होंने हवाला दिया कि जिस दवा की कीमत 100 रुपये होती है वह आज केवल 20 रुपये में उपलब्ध है। ■

शाहपुरा, (राजस्थान)

'नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा भारत का कद'

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भर्ती परीक्षा पेपर लीक और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर प्रहार किया। 19 नवंबर, 2023 को राजस्थान के शाहपुरा में एक विशाल चुनावी रैली में अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "जो कोई माताओं और बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकता, उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।"

श्री सिंह ने कहा कि चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश बनाने के लिए भी लड़ा जाता है। उन्होंने कहा, "सरकार जाति, पंथ और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर चलनी चाहिए।''

रक्षा मंत्री ने कहा, ''भारत अब कमजोर नहीं है और दुनिया उसकी बात ध्यान से सुनती है और श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ा है।''

"पहले, जब भारत कुछ कहता था, तो दुनिया के देश हमें एक कमजोर राष्ट्र मानकर हमारी राय को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब आप गर्व कर सकते हैं कि पूरी दुनिया अपनी बात कहने के लिए भारत की ओर देखती है।''

हमने अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था

केंद्र कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए श्री सिंह ने कहा, "हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का वादा किया था और हमने ऐसा करके भी दिखाया। हमने वादा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा और अब आप सभी को 22 जनवरी को भगवान राम के दर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है।

इसके अलावा, प्रदेश के चुनाव घोषणापत्र में उल्लिखित सभी गारंटियों को पूरा करने का वादा हम करते हैं। "अब भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमने अपने घोषणापत्र में जो भी वादा किया है, अगर हमें मौका दिया गया, तो हम उल्लिखित सभी वादों को पूरा करेंगे।" ■

वारंगल एवं जगतियाल (तेलंगाना)

घोटालेबाज केसीआर सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 20 नवंबर, 2023 को तेलंगाना के वारंगल (जनगांव विधानसभा) और जगतियाल (कोरातला विधानसभा) में आयोजित विशाल रैलियों को संबोधित किया और राज्य की जनता से घोटालेबाज और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार करनेवाली केसीआर सरकार को बाहर का रास्ता दिखाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास, विकास और केवल विकास को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमतवाली सरकार बनाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना को आजाद करने के लिए देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने संकल्प लिया था कि देश को निज़ामों से मुक्त करना जरूरी है। उन्होंने केसीआर पर निशाना साधते कहा कि ओवैसी के डर से केसीआर ने हैदराबाद विमोचन दिन मनाने से मना कर दिया। भाजपा ने तय किया हैं कि तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रतिवर्ष 17 सितंबर को 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनाया जाएगा व तेलंगाना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही, वीरनापल्ली व पारकाल के शहीदों के अतुलनीय योगदान को चिरस्मरणीय बनाए रखने हेतु उनके सम्मान में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने पर हर साल 27 अगस्त को 'विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मनाया जाएगा।

केसीआर, ओवैसी और राहुल गांधी की पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि केसीआर की पार्टी, ओवेसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। ये तीनों पार्टियां 2G, 3G, और 4G पार्टियां हैं, 2G का मतलब है केसीआर और केटीआर, 3G का मतलब है ओवैसी की पार्टी और 4G का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न 2G, न 3G, न 4G पार्टी है, यह तेलंगाना की जनता की पार्टी है।

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री का चुनाव पिछड़ा वर्ग से किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय किया है कि आगामी दिनों में मडिगा समाज के लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित के करने साथ ही उनको वर्टिकल आरक्षण देने का कार्य करेंगे। ■

मसूदा, (राजस्थान)

'विकास के लिए कमल के फूल की सरकार बनाना बहुत जरूरी'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 नवंबर, 2023 को राजस्थान के मसूदा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने राजस्थान की जनता से कहा कि आनेवाले विधानसभा चुनाव के दिन किसी को विधायक बनाने या भाजपा की सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाकर राजस्थान और देश को खुशहाल करने के लिए मतदान करें।

श्री शाह ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने 'टोटल भ्रष्टाचार' नहीं किया होगा, उतना घोटाला अकेले गहलोत सरकार ने केवल 5 वर्षों में किया है। सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर रही है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार सबसे भ्रष्ट है। गहलोत सरकार ने खनन विभाग में 66000 करोड़ रुपए, खनन के पट्टे देने में 1000 करोड़ रुपए, उदयसागर झील में 2000 करोड़ रुपए, प्रतापगढ़ की चुना पत्थर खदान में 1000 करोड़ रुपए, कालीसिंध बांध में 250 करोड़ रुपए और गेहू-बाजरे के आवंटन में भी 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। गहलोत सरकार के सचिवालय की अलमारियों से 2 करोड़ रुपए और किलो के हिसाब में सोना जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है गहलोत सरकार को उखाड़कर, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को राजस्थान के विकास के लिए लाया जाए। भ्रष्टाचार में तो राजस्थान नंबर एक पर ही थी, साथ ही यह अशोक गहलोत की वजह से तुष्टीकरण और महिला अत्याचार में भी नंबर एक पर है। आज राजस्थान बिजली की दरों, साइबर क्राइम, महंगाई इंडेक्स, पेपर लीक मामलों में सभी बुराइयों में नंबर 1 पर है।

श्री शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में सोनिया-मनमोहन की सरकार 10 वर्ष तक थी, फिर भी राजस्थान को केवल 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किये गए। वही दूसरी ओर मोदीजी ने 9 वर्षों में 8 लाख 71 हजार करोड़ रुपए राजस्थान के विकास के लिए आवंटित किये हैं। राजस्थान का विकास लाल डायरी में हिसाब रखनेवाली कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। श्री शाह ने अंत में राजस्थान की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि राजस्थान को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए कमल के फूल की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। ■

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव : भाजपा संकल्प पत्र का विमोचन

भाजपा अपने संकल्प पत्र का अक्षरशः कार्यान्वयन करती रही है और आगे भी किये गए सभी वादे पूरा करेगी: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 नवंबर, 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिन्टों हॉल, भोपाल (मध्य प्रदेश) में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी एवं मंत्री उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का अक्षरशः कार्यान्वयन करती रही है और आगे भी किये गए सभी वादे पूरा करेगी।

प्रमुख बातें—

- मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनर्स्थापना के बाद गांव की बहनों को लखपति बनाने के लिए 'विशेष प्रशिक्षण एवं कौशल विकास' के कार्य भाजपा सरकार करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 21 वर्ष आयु की 2 लाख से अधिक बहनों को कौशल सम्पन्न बनने की मदद के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
- किसान भाइयों के लिए भाजपा सरकार गेहूं की खरीद 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और धान की खरीद 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर करेगी। केंद्र सरकार किसानों को सालाना 12,000 रुपए 'किसान सम्मान निधि' परियोजना के अंतर्गत दे रही है, उसे 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि' के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा।
- मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय कल्याण व उनके सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट भाजपा आवंटित करेगी। तेंदुपत्ता संग्राहक वर्ग के लिए भाजपा प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए देगी।
- हर अनुसूचित जाति ब्लॉक में एक एकलव्य विद्यालय व एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भाजपा ने लिया है। मध्य प्रदेश में सभी गरीब परिवार के बच्चों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। भाजपा प्रत्येक मंडल में एक आईआईटी कॉलेज खोलेगी। एम्स की तर्ज पर प्रदेश में मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी खोला जाएगा।
- मध्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का कार्य किया जाएगा। गरीब वर्ग के मद्देनजर गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक गेहूं, चावल, दाल दिया जाता था, किन्तु आनेवाले समय में भाजपा सरसों-तेल व चीनी भी रियायती दरों में प्रदान कराएगी।
- आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए 6 नए एक्सप्रेस वे- विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल प्रगति एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे व मध्य भारत विकास पथ बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार 34 रेलवे स्टेशन को सबसे आधुनिक तरीके से नवीन स्वरूप दे रही है। साथ ही 2 नए विश्व स्तरीय हवाई अड्डे, रीवा व सिंहरौली में बन रहे है, उनको भी जनता को जल्द सौंपा जाएगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का पूर्व परीक्षण हो चुका है। भाजपा ग्वालियर, जबलपुर में भी मेट्रो रेल लाने के लिए संकल्परत है।
- स्वास्थ्य जगत में एक नवीन पहल के रूप में 'अटल मेडिसिटी' बनाने की परिकल्पना भाजपा ने की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अलग से 20 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- सांस्कृतिक विकास हेतु 13 सांस्कृतिक लोक निर्माण व नवीनीकरण का काम भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जोड़ा है। 13 पावन स्थल के नवीनीकरण का कार्य भाजपा आनेवाले 5 वर्षों में सम्पन्न करके जनता के सामने रखेगी। ■

राजस्थान विधानसभा चुनाव : भाजपा संकल्प पत्र का विमोचन

'भाजपा संकल्प पत्र विकास का रोडमैप है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 नवंबर, 2023 को जयपुर, राजस्थान में राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान के प्रभारी श्री अरुण सिंह, केन्द्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि बाकी दलों के लिए संकल्प पत्र मात्र एक औपचारिकता है, लेकिन भाजपा के लिए यह विकास का रोडमैप है। भाजपा इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा का

इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाजपा ने अपने किए सभी वादे पूरे किए हैं और जो वादे नहीं भी किए थे उसे भी पूरा करके दिखाया है।

प्रमुख बातें:

- महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा, हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और उसी तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हे मुख्यधारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया जाएगा।
- लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख से ऊपर ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आगे बढ़ सके। उज्ज्वला धारकों को प्रत्येक सिलिन्डर पर 450 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे घरों में राहत और महिलाओं के विकास का प्रयास किया जाएगा। मातृ वंदन योजना के तहत देखरेख के लिए दिए जाने वाले 5000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया जाएगा। उसी तरह से स्कूल जाने वाले वे छात्र-छात्राएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सरकार द्वारा उन्हें 1200 रुपए डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि वह बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म, पुस्तकें खरीद सकें और स्कूल जा सकें।
- अगर भाजपा की सरकार राज्य में आती है तो सरकार द्वारा एक विशेष जांच कमेटी बनाई जाएगी और राजस्थान पेपर लीक मामले एवं सभी घोटालों में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा की दोषियों को दंड दिया जाए।
- टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का कॉरपस फंड सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसमें टूरिज्म के सुविधाओं से लेकर, उससे जुड़े लोगों की स्किल ट्रैनिंग से लेकर, टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए 5 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाने का प्रयास किया जाएगा।
- एम्स और आईआईटी की तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी और राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला जाएगा।
- राज्य में 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी युवाओं के लिए मुहैया कराई जाएगी।
- गरीबों के कल्याण के लिए अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चालू रहेगी, इसी के साथ-साथ भामाशाह हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च किये जाएंगे और हेल्थ सिस्टम में सुधार के प्रयास किये जाएंगे, इसके साथ-साथ 15,000 डॉक्टर्स और 20,000 पेरामेडिक्स की नियुक्ति की व्यवस्था भाजपा सरकार द्वारा की जाएगी।
- कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रीजनल हेरिटेज सेंटर विकसित किये जाएंगे जिसमें 800 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे, इसमें लोकल कल्चर, लोक नृत्य, लोक गीत, लोकल लिटरेचर, लोकल ड्रेस से लेकर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। शेखावटी, धुंधार, मेवार, मारवाड़, धानौती, अजमेर और बीकानेर के कल्चर को प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा।
- मानगढ़ धाम को विकसित करने के साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि आदिवासी भाइयों की कुर्बानी के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो सके।
- अनुसूचित जातिओं और ट्राइबल कल्चर ने किस तरह से भारत भूमि की रक्षा में योगदान दिया यह भी चित्रित करने का प्रयास किया जाएगा। ■

भाजपा हर वर्ष 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के तौर पर मनाएगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 नवंबर, 2023 को हैदराबाद में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा विजन डॉक्यूमेंट-2023 जारी किया। भाजपा विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने के बाद श्री शाह ने कहा कि घोषणापत्र में किए गए वादे जनता को 'प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी' हैं। पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार भाजपा ने हर साल 17 सितंबर को आधिकारिक तौर पर 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के तौर पर मनाने का फैसला किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वे हमेशा से तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री श्री मोदी की तेलंगाना को गारंटी है।"

प्रमुख बातें:

- हर साल 17 सितंबर को 'हैदराबाद लिबरेशन डे' मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से नई पीढ़ी को तेलंगाना की निजाम की क्रूर नीतियों के मुक्ति को याद कराया जाएगा।
- वैरनपल्ली परकन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 अगस्त को 'रजाकार विभीषिका स्मृति दिवस' भी मनाया जाएगा। ये दोनों दिन तेलंगाना सरकार मनाएगी और मजलिस से नहीं डरेगी।
- भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाएगी और दोषियों को जेल की सलाखों की पीछे डाला जाएगा।
- पिछड़ा वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से होगा।
- 4 प्रतिशत के असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण को खत्म किया जाएगा तथा ओबीसी, एससी और एसटी का जनसंख्या अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा।
- एससी के अधिकांश वंचित और वंचित लोग सशक्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण हेतु फास्ट ट्रैक व्यवस्था की जाएगी।
- भाजपा की सरकार बनने पर 7 दिन के अंदर वैट कम कर पेट्रोल, डीजल की कीमतें सस्ती की जाएंगी।
- छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक की सहायता के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की गई।
- किसानों के हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना कर मूल संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, तेलंगाना के किसानों के लिए धान पर 3100 रुपये एमएसपी और हल्दी पर मार्केट इंटर्वेशन फंड प्रदान किया जाएगा।
- सरकार बनने पर जिस जाड़ा चावल को तेलंगाना की बीआरएस सरकार खरीदने से मना करती है, उसे भाजपा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुफ्त में फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा।
- तेलंगाना में भाजपा की सरकार गठित होने पर उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 4 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे।
- बेटी के जन्म पर एक 2 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपोजिट का तोहफा दिया जाएगा जो पैसा बेटी के 21 वर्ष के होने पर उसे मिलेगा।
- स्नातक, डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सेज में अध्ययनरत छात्रों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
- भाजपा की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होगा और 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी।
- सीमांत किसानों की जीवनयापन को और आसान के लिए इच्छुक किसानों को मुफ्त में गाय दी जाएंगी।
- सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक हेल्थकेयर के लिए प्रति वर्ष, प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- तेलंगाना को पानी उचित हिस्सा दिलाने के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष के मामले को उचित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
- तेलंगाना में भाजपा की बनने पर प्रदेश में यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड/ समान नागरिक संहिता) लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो 6 महीने में प्रदेश में यूसीसी लागू करेगी।
- प्रदेश में बिना घर के सभी लोगों के केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर समयबद्ध तरीके घर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, गांव में गरीब लोगों को आवास स्थल के पट्टे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ■

भाजयुमो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, नई दिल्ली

'मंडल सशक्तीकरण अभियान' का शुभारंभ

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 04 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और देशभर के कार्यकर्ता को मार्गदर्शन प्रदान करना रहा।

कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, "आगामी छह महीनों में भाजयुमो की एकमात्र प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश की सेवा करने का एक और मौका मिले। वहीं, उन्होंने आगे कहा कि यह पार्टी अब एक आंदोलन में बदल गयी है, जो समाज के वंचितों की भलाई के लिए काम कर रही है।"

एक अन्य सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री शिवप्रकाश ने संबोधित किया, जिन्होंने अपनी बात में संगठन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "भाजयुमो कार्यकर्ताओं का मुख्य काम आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में शिक्षित करना, लोगों को नीतियों का पूरा लाभ उठाने में मदद करना और यह सोचना होना चाहिए कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जा सकता है।" इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैसे मंडल टीमें पूरी तरह सक्रिय रहें, हमें राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने होंगे और विस्तारकों को नौ दिनों के मंडल प्रवास पर जाना चाहिए।" इसके बाद के सत्र में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल ने युवा मोर्चा के सदस्यों को निर्विरोध राजनीतिक जीत का रोडमैप समझाया। उन्होंने कहा, "2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद समाचारों की सुर्खियां इस जीत में युवाओं के महत्व को उजागर करेंगी। इस लोकसभा चुनाव में लगभग दो करोड़ नये युवा मतदाता होंगे।''

समापन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भाजयुमो का 'विद्या कमल ऐप' लॉन्च किया। यह ऐप एक ई-लर्निंग मोबाइल ऐप होगा, जो जनता को नवीनतम समाचारों, नेताओं के बारे में जानकारी और नवीनतम पोस्ट से भी जोड़ेगा। श्री गोयल ने कहा, "एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में हम छोटे-छोटे काम करके जो चीजें सीखते हैं, वह बड़े पद पर आने के बाद नहीं सीख सकते। युवा मोर्चा में आप युवा हैं और आपको इस स्तर पर सीखना चाहिए।"

इस कार्यकारिणी बैठक में सशक्तीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई एक दूरदर्शी पहल है। 'मंडल सशक्तीकरण अभियान' में हमारे प्रदेश टीम के सदस्यों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए एक 'प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' भी शामिल है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या ने 'मंडल सशक्तीकरण अभियान' की सफलता पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "सुधार करें, प्रदर्शन करें, परिवर्तन करें और सूचित करें। यह मोदी सरकार का एजेंडा है। हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और इसकी सेवा करना हमारा ध्येय है।"

भारत का कुल निर्यात अक्टूबर, 2023 में 62.26 बिलियन डॉलर होने का अनुमान

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर, 2023 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं संयुक्त) 62.26 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर, 2022 की तुलना में 9.43 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अक्टूबर, 2023 में कुल आयात 79.35 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो अक्टूबर, 2022 की तुलना में 11.10 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

अक्टूबर, 2023 में वस्तु वस्तुओं का निर्यात 33.57 बिलियन डॉलर था, जबकि अक्टूबर, 2022 में यह 31.60 बिलियन डॉलर था। अक्टूबर, 2023 में वस्तु आयात 65.03 बिलियन डॉलर था, जबकि अक्टूबर, 2022 में यह 57.91 बिलियन डॉलर था।

अक्टूबर, 2023 में गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 24.57 बिलियन डॉलर था, जबकि अक्टूबर, 2022 में यह 21.99 बिलियन डॉलर था। अक्टूबर, 2023 में गैर-पेट्रोलियम, गैर-रत्न और आभूषण (सोना, चांदी और कीमती धातु) का आयात 36.87 बिलियन डॉलर था, जबकि अक्टूबर, 2022 में यह 35.12 बिलियन डॉलर था।

अक्टूबर, 2023 के लिए सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 28.70 बिलियन डॉलर है, जबकि अक्टूबर, 2022 में यह 25.30 बिलियन डॉलर था। अक्टूबर, 2023 के लिए सेवाओं के आयात का अनुमानित मूल्य 14.32 बिलियन डॉलर है, जबकि अक्टूबर, 2022 में यह 13.51 बिलियन डॉलर था।

अप्रैल-अक्टूबर 2023 के लिए सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 192.65 बिलियन डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2022 में यह 181.37 बिलियन डॉलर था। अप्रैल-अक्टूबर 2023 के लिए सेवाओं के आयात का अनुमानित मूल्य 103.22 बिलियन डॉलर है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2022 में यह 104.09 बिलियन डॉलर था। अप्रैल-अक्टूबर 2023 के लिए सेवा व्यापार अधिशेष 89.43 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल-अक्टूबर 2022 में यह 77.28 बिलियन डॉलर था। ■

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9 नवंबर, 2023 तक 17.59 प्रतिशत बढ़कर 12.37 लाख करोड़ रुपये रहा

रिफंड के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह 10.60 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21.82 प्रतिशत अधिक है। वर्ष दर वर्ष के आधार पर कॉरपोरेट आयकर संग्रह और व्यक्तिगत आयकर संग्रह में कुल वृद्धि क्रमशः 12.48 प्रतिशत और 31.77 प्रतिशत रही

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार 9 नवंबर, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.37 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 17.59 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह 10.60 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21.82 प्रतिशत अधिक है। यह संग्रह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजटीय अनुमान का 58.15 प्रतिशत है।

जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉरपोरेट आयकर (सीआईटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) की वृद्धि दर का सवाल है, सीआईटी के लिए वृद्धि दर 7.13 प्रतिशत है जबकि पीआईटी के लिए वृद्धि दर 28.29 प्रतिशत (केवल पीआईटी)/27.98 प्रतिशत (प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) सहित पीटीआई) है।

रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में कुल वृद्धि 12.48 प्रतिशत है और पीआईटी संग्रह में 31.77 प्रतिशत (केवल पीआईटी)/31.26 प्रतिशत (एसटीटी सहित पीआईटी) है। 1 अप्रैल, 2023 से 09 नवंबर, 2023 के दौरान 1.77 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए। ■

अक्टूबर, 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.87 प्रतिशत हुई

महंगाई निरंतर कम हो रही है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार सब्जियों समेत अन्य खाने का सामान सस्ता होने से अक्टूबर, 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति चार महीने के निचले स्तर 4.87 प्रतिशत पर आ गयी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) सितंबर में तीन महीने के निचले स्तर 5.02 प्रतिशत पर थी। इससे पहले, जून में महंगाई दर 4.87 प्रतिशत दर्ज की गयी थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई अक्टूबर महीने में घटकर 6.61 प्रतिशत रही। यह सितंबर में 6.62 प्रतिशत और एक साल पहले सात प्रतिशत थी। सब्जियों, मांस और मछली तथा ईंधन के मामले में महंगाई कम रही। ■

सितंबर, 2023 में ईएसआई योजना के तहत 18.88 लाख नए श्रमिकों का किया गया नामांकन

नए पंजीकरण में 25 वर्ष की आयु वर्ग के 9.06 लाख युवा कर्मचारी शामिल। ईएसआई योजना में 3.51 लाख महिला कर्मचारी नामांकित हैं। सितंबर, 2023 में ईएसआई योजना के तहत लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अस्थायी पेरोल डेटा के अनुसार सितंबर, 2023 के महीने में 18.88 लाख नए कर्मचारी ईएसआई योजना के तहत शामिल किए गए हैं। सितंबर, 2023 में लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया और इनके कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके अधिक कवरेज सुनिश्चित की गई।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार उपलब्ध डेटा से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देश के युवाओं के लिए अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है क्योंकि इस माह के दौरान शामिल किए गए कुल 18.88 लाख कर्मचारियों में से 9.06 लाख कर्मचारी 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जिनकी नए पंजीकरणों में बहुतायत है और जो कुल कर्मचारियों के 47.98 प्रतिशत हैं।

पेरोल डेटा के जेंडर-वार विश्लेषण से पता चलता है कि सितंबर, 2023 में कुल 3.51 लाख महिला सदस्यों का नामांकन हुआ है। डेटा से पता चलता है कि कुल 61 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी सितंबर, 2023 में ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराया है जो यह दर्शाता है कि ईएसआईसी अपनी ईएसआई योजना का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

पिछले 9 वर्ष में एमबीबीएस सीटों में 79 प्रतिशत और एमडी में 93 प्रतिशत की हुई वृद्धि

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 10 नवंबर को कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, ताकि कोई योग्य उम्मीदवार स्वयं को नुकसान में महसूस न करे। उन्होंने कहा कि केवल 9 वर्ष में एमबीबीएस सीटों की संख्या 79 प्रतिशत बढ़कर 51,348 से 91,927 हो गई, जबकि एमडी सीटों की संख्या 93 प्रतिशत बढ़कर 31,185 से 60,202 पर पहुंच गई।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एक लंबी छलांग लगाते हुए 2014 में 145 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से बढ़कर भारत में अब 260 जीएमसी हैं, जबकि 9 वर्ष में देश में एम्स की संख्या 23 हो गई है। ■

भारत ने 2023-34 में अभी तक रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट दिए

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस वित्त वर्ष में 15 नवंबर तक 'सर्वाधिक' 41,010 पेटेंट प्रदान किए हैं। श्री गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''यह एक रिकॉर्ड है। 2023-24 में सर्वाधिक पेटेंट दिए गए।"

श्री पीयूष गोयल की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो नवाचार-संचालित ज्ञान अर्थव्यवस्था की दिशा में हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर है। भारत के युवा इस तरह की प्रगति के बड़े लाभार्थी बनेंगे। ■

एमएसएमई क्षेत्र में 15 करोड़ से अधिक रोजगार का हुआ सृजन

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 10 नवंबर को जारी एक बयान के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र ने 15 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री नारायण राणे ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि की घोषणा एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में की।

श्री राणे ने उद्यम पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयों के पंजीकरण के साथ इस उपलब्धि को सुगम बनाने में उद्यम पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें उद्यम असिस्ट पोर्टल पर पंजीकृत 99 लाख अनौपचारिक एमएसएमई इकाइयां शामिल हैं। इन 3 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई में 41 लाख से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई हैं।

श्री राणे ने एमएसएमई क्षेत्र में महिला कामगारों के महत्वपूर्ण योगदान पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रोजगार अवसर जो पैदा किये गए हैं, उनमें 3.4 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। यह एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ■

ईपीएफओ ने सितंबर, 2023 के दौरान कुल 17.21 लाख सदस्यों को जोड़ा

20 नवंबर को जारी ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ ने सितंबर, 2023 में 17.21 लाख सदस्यों को जोड़ा। पेरोल आंकड़ों को महीने-दर-महीने देखें तो अगस्त, 2023 की तुलना में सितंबर, 2023 में 21,475 सदस्यों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, साल-दर-साल के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर, 2022 की तुलना में सितंबर, 2023 में कुल 38,262 सदस्यों की बढ़ोतरी हुई।

पेरोल के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर, 2023 के दौरान लगभग 8.92 लाख नए सदस्यों ने नामांकन किया है। इन नए शामिल हुए सदस्यों में 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों की कुल हिस्सेदारी 58.92 फीसदी है। इससे पता चलता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य युवा हैं, जिनमें ज्यादातर पहली बार नौकरी चाहने वाले हैं।

उद्योग-वार आंकड़ों की महीने-दर-महीने तुलना बताती है कि चीनी उद्योग, कूरियर सेवाओं, लोहा व इस्पात, अस्पतालों, यात्रा एजेंसियों आदि में सदस्यों की संख्या में विशिष्ट बढ़ोतरी हुई है। कुल सदस्यता में से लगभग 41.46 फीसदी अतिरिक्त विशेषज्ञ सेवाओं (जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं, सामान्य ठेकेदारों, सुरक्षा सेवाओं, विविध गतिविधियों आदि से मिलकर) से संबंधित है। ■

मोदी स्टोरी

नरेन्द्र मोदीः प्रतिकूलता को अवसर में बदलना

— थिरुपुगाज

प्रतिकूल परिस्थितियों में सच्चे नेता न केवल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रबंधन करने, बल्कि उन्हें विकास और नवाचार के अवसरों में बदलने की उल्लेखनीय क्षमता के साथ उभरते हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हीं स्थितियों के लिए 'आपदा में अवसर' का मुहावरा दिया और इन सभी वर्षों में अपने कार्यों से इसे साबित भी किया। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मोदी ने प्रतिकूलताओं को अवसरों में बदलने की अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

2001 का गुजरात भूकंप भारत की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। इस भूकंप में 13,805 लोगों की जान गई, 19 जिले समेत 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। कच्छ, भुज, बचाऊ, अंजार और रोपड़ जैसे क्षेत्र 95 प्रतिशत तक ध्वस्त हो गये थे। इस भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्य सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। लगभग 12 लाख घरों, 42,000 स्कूल के कमरों, 10,000-12,000 स्कूलों की या तो मरम्मत की जानी थी या अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाना था। लाखों लोगों की आजीविका को पटरी पर लाना था।

सेवानिवृत्त आईएएस श्री थिरुपुगाज याद करते हैं कि इस दौरान पुनर्निर्माण नीतियों की घोषणा की गई। इनका कार्यान्वयन धीरे-धीरे बढ़ रहा था और उस समय श्री मोदी ने कार्यभार संभाला ही था। उन्होंने प्रगति की समीक्षा की और देरी के मामलों पर सख्ती की। उन्होंने कहा, 'हम पुनर्निर्माण करेंगे, हम निश्चित रूप से प्रगति करके दिखाएंगे।' उन्होंने प्रत्येक प्रभावित तालुका को एक सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपने जैसे अभिनव कदम उठाए। उन्होंने सचिवों से कहा कि गांधीनगर स्थित सचिवालय में बैठने का कोई मतलब नहीं है। सभी को मैदान में जाने के लिए निर्देशित किया गया। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सचिवों को अपने निर्धारित तालुका में जाना होता था और सोमवार सुबह मुख्यमंत्री श्री मोदी प्रगति का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक करते थे। श्री मोदी ने उन्हें पर्याप्त शक्तियां भी दीं; उन्हें वहां जाने और मौके पर ही निर्णय लेने की अनुमति दी गई। इस प्रकार, उन्होंने सत्ता को विकेंद्रीकृत करके प्रणाली को सशक्त बनाने की चुनौती को एक अवसर में बदल दिया ताकि आपदा प्रबंधन अधिक स्थानीयकृत और भागीदारीपूर्ण हो सके।'

एक और बड़ी चुनौती जिसका सामना करना पड़ा रहा था, वह थी कि हमारे सामने सीखने के लिए पुनर्निर्माण का कोई मॉडल उपलब्ध नहीं था। फिर, सहभागी दृष्टिकोण पर आधारित नए शहर और विकासात्मक योजना को अपनाया गया। इस योजना का उत्कृष्ट पहलू मालिक द्वारा संचालित पुनर्निर्माण कार्यक्रम था। इस प्रकार, डोनर-संचालित (ऊपर-नीचे दृष्टिकोण) के बजाय, नीचे-ऊपर दृष्टिकोण अपनाया गया।

इसलिए मुख्यमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में इन सभी चुनौतियों पर काबू पाया गया। इंजीनियरों और निगरानी एजेंसियों की भर्ती की गई, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया और सामग्री बैंक बनाए गए। तो, अंततः यह मालिक-संचालित पुनर्निर्माण कार्यक्रम एशियाई देशों के लिए अंतिम मॉडल बन गया। इस प्रकार, इस विशाल चुनौती से दुनिया को एक वैश्विक मॉडल देने का अवसर तैयार हुआ।

एक और घटना है जो दर्शाती है कि श्री नरेन्द्र मोदी न केवल स्थिति को संभालते हैं बल्कि उसे पलट देते हैं और विपरीत परिस्थिति में भी अवसर ढूंढ़ लेते हैं। प्रशासन कच्छ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए एक स्मारक बनाने की योजना बना रहा था। कुछ जापानी और स्मारकों के अन्य मॉडलों को देखा गया। श्री नरेन्द्र मोदी जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के लिए एक पेड़ लगाने के सबसे नवीन विचारों में से एक लेकर आए और फिर 13,805 पेड़ लगाए गए और प्रत्येक पेड़ उस व्यक्ति को समर्पित किया गया, जिसने अपनी जान गंवाई थी। उनका विचार था कि परिवार साल में एक बार आएंगे और अपने पेड़ का रखरखाव करें और इस पेड़ को वह अपनी परिजन के तौर पर अपनाए।

उन्होंने इसका नाम स्मृति वन रखा, जो कि जान गंवाने वाले लोगों के नाम पर उनकी याद में एक क्षेत्र था और इसीलिए इसे स्मृति वन कहा जाता है।

श्री नरेन्द्र मोदी की विरासत नेतृत्व के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में खड़ी है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच पनपती है, शासन और आपदा प्रतिक्रिया के परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। प्रतिकूलता को अवसर में बदलने की उनकी क्षमता प्रेरणा की किरण के रूप में हम सभी के समक्ष है। ■

राष्ट्र निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन राष्ट्र और दीन-हीनों की सेवा के लिए समर्पित था। उनके सामने जहां एक तरफ करोड़ों दुःखी-पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न था, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र हित का सतत संवर्धन भी था। डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तित्व सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका योगदान समूचे भारत के लिए था। वे पूरे भारत के नेता थे। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के हित में काम किया।

अपनी माता-पिता की चौदहवीं संतान के रूप में जन्मे डॉ. भीमराव अम्बेडकर (14 अप्रैल, 1891 — 06 दिसंबर, 1956) जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात् आर्थिक कारणों से वह सेना में भर्ती हो गए। उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर बड़ौदा में तैनाती मिली। अपने मित्र कैलुस्कर की प्रेरणा और महाराजा बड़ौदा की आर्थिक मदद से भीमराव उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उन्होंने अपनी अध्ययनशीलता का परिचय दिया। 1917 में डॉ. अम्बेडकर भारत लौटे और देश सेवा के महायज्ञ में अपनी आहुति डालनी शुरू की। महाराजा कोल्हापुर के सहयोग से उन्होंने मराठी में 'मूक नायक' नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया। वह 'बहिष्कृत भारत' नामक पाक्षिक तथा 'जनता' नामक साप्ताहिक के प्रकाशन तथा संपादन से भी जुड़े।

उन्होंने विचारोत्तेजक लेख लिखकर लोगों को जगाने का प्रयास किया। डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। उन्होंने देश के दलित वर्ग को मुखर होने की ताकत दी। 'संविधान प्रारूप समिति' के अध्यक्ष के रूप में वह भारतीय संविधान के निर्माता बने। मार्च 1952 मे उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और वे अंत तक इस सदन के सदस्य रहे। 6 दिसंबर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न'के अलंकरण से सम्मानित किया।

बाबा साहब का जीवन इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ही उसका निर्माण करता है, उसकी जाति, पारिवारिक निर्धनता, असुविधाएं और समाज का विरोध उसकी प्रगति को रोक नहीं सकता। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन युवकों के लिये प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने देश की युवा शक्ति से परिश्रमी तथा गुण संपन्न बनने का आहवान किया। बाबा साहब कहते हैं- 'सम्मान की आकांक्षा करना कोई पाप नहीं है, परंतु कार्य करते-करते सम्मान प्राप्त नहीं होता है, तो निराश होकर आप संघर्ष मत छोड़िये। यदि दुर्भाग्य से आप उस सम्मान से वंचित कर दिये जाये जिसके वास्तविक अधिकारी आप है फिर भी आप धैर्य न छोड़ें

राष्ट्रहित सर्वोपरि

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। इसलिये वे मुस्लिम विघटनकारी शक्तियों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उनमें हिन्दुओं के साथ सह-अस्तित्व की बुनियादी भावना का अभाव है। इसके बिना देश की उन्नति असंभव है, इसी परिप्रेक्ष्य में सन् 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग पर अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे पठनीय हैं। डॉ. साहब ने वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अंग्रेजों के इस दुष्प्रचार का खण्डन किया कि आर्य इस देश में बाहर

से आए थे, तथा वर्तमान के शूद्र लोग आर्य नहीं हैं। उन्होंने यह बात आग्रहपूर्वक कही कि आर्य कोई वंश नहीं है तथा आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। उन्होंने यह सुस्थापित किया कि शूद्र भी आर्य हैं। इस प्रकार आर्यों के बाहर से आने वाले सिद्धांत को उन्होंने मनगढ़ंत और निराधार बताया।

बाबा साहब का जीवन इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ही उसका निर्माण करता है, उसकी जाति, पारिवारिक निर्धनता, असुविधाएं और समाज का विरोध उसकी प्रगति को रोक नहीं सकता। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन युवकों के लिये प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने देश की युवा शक्ति से परिश्रमी तथा सर्वगुण संपन्न बनने का आहवान किया। बाबा साहब कहते हैं- 'सम्मान की आकांक्षा करना कोई पाप नहीं है, परंतु कार्य करते-करते सम्मान प्राप्त नहीं होता है, तो निराश होकर आप संघर्ष मत छोड़िये। यदि दुर्भाग्य से आप उस सम्मान से वंचित कर दिये जाये जिसके वास्तविक अधिकारी आप है फिर भी आप धैर्य न छोड़ें।'

डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक और राजनैतिक सुधारों का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच का सारे राजनीतिक हलकों में काफी सम्मान हासिल हुआ। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज के भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक, आर्थिक नीतियों, शिक्षा, कानून और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित होती है। संविधान निर्माण के महान राष्ट्रीय कार्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। डॉ. अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना कि लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। मसौदा तैयार करते समय डॉ. अम्बेडकर ने अपनी विद्वता और कार्य निष्ठा के चलते अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की काफी प्रशंसा अर्जित की।

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा, 'मैं महसूस करता हूं कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।'

24 सितम्बर, 1932 को गांधी से पूना संधि करके डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्र की एकता को और मजबूत किया। 24 सितम्बर, 1932 को सर तेज बहादुर सप्रू ने गांधी और डॉ. अम्बेडकर से मिलकर एक समझौता तैयार किया जिसमें डॉ. अम्बेडकर को पृथक निर्वाचन की मांग को वापस लेना था और गाँधी जी के दलितों को केन्द्रीय और राज्यों की विधान सभाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में दलितों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देना एवं सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व देना था। इसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं में दलितों को विशेष सुविधाएं देना भी था। दोनों नेता इस समझौते पर सहमत हो गये। 24 सितम्बर, 1932 को इस समझौते पर गांधी जी और डॉ. अम्बेडकर ने तथा इनके सभी समर्थकों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते को 'पूना पैक्ट' कहा गया। पूना पैक्ट में ही दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उनके उन्नति की आधारशिला बनी। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

कृष्ण गोपाल लुनानी

राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश निवासी श्री कृष्ण गोपाल लुनानी अपनी युवावस्था के दौरान 1952 में भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। तब से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किया। उन्होंने जनसंघ में काकीनाडा शहर के संयुक्त मंत्री, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद् सदस्य सहित कई दायित्वों का निर्वहन किया। श्री लुनानी आपातकाल के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे और मीसा के तहत 18 महीने के लिए राजमुंदरी केंद्रीय जेल में कैद रहे। श्री लुनानी ने 1980 में जनता पार्टी के जिला मंत्री बने और बाद में भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद पार्टी के जिला मंत्री रहे। ■

कृष्ण गोपाल लुनानी

जन्म: 05 अक्टूबर, 1936
सक्रिय वर्ष: 1952-2021
जिला: गोदावरी पूर्व, आंध्र प्रदेश

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका

एस. जयशंकर

हम जब वर्ष 2023 पर एक नजर डालते हैं, तो इस दौरान जी-20 की अध्यक्षता और चंद्रयान-3 मिशन निश्चित रूप से भारत की प्रमुख उपलब्धियों में शुमार होते हैं। यह घटनाक्रम कोविड-19 के बाद भारत के संभलने और मजबूत विकास से प्रेरित राष्ट्रीय मनोदशा की ओर इशारा करते हैं।

भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 सम्मेलन का फोकस तरक्की और विकास की चुनौतियां रहा। इसे सतत विकास लक्ष्यों, हरित विकास समझौते, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्ययोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) सभा का आयोजन अफ्रीकी संघ (एयू) की स्थायी जी-20 सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्तावना थी।

पिछले दशक में भारत के 'पड़ोसी प्रथम' दृष्टिकोण ने नये संपर्कों को स्थापित करने और संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। श्रीलंका के आर्थिक संकट पर त्वरित प्रतिक्रिया ने महामारी के दौरान दिये जाने वाले समर्थन को अधिक विस्तृत किया है। 'विस्तारित पड़ोस' की नीति के कारण आसियान, खाड़ी, मध्य एशिया और हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति सुदृढ़ हुई है। प्रशांत महासागर से लेकर कैरेबियन तक हमारी पहलों ने भारत की पहुंच को अधिक विस्तार दिया है।

वर्ष 2023 के दौरान भारत ने इस बात को मजबूती से रखा कि यूक्रेन के आसपास पूर्व-पश्चिम ध्रुवीकरण को कैसे पार किया जाए और उत्तर-दक्षिण विकासात्मक विभाजन को कैसे पाटा जाए। विषम वैश्वीकरण, कोविड क्षति, यूक्रेन में संघर्ष, बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन और अब मध्य पूर्व में हिंसा के प्रभाव ने निश्चित रूप से दुनिया को कहीं अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित बना दिया है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उभरने के लिए फुर्तीली और 'मल्टी-वेक्टर' भारतीय कूटनीति की आवश्यकता है। सहमत मुद्दों पर अपने साझेदारों के साथ क्वाड तंत्र, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ब्रिक्स विस्तार और रचनात्मक मध्य पूर्व पहल में काम करना स्वाभाविक था।

वर्ष 2023 के दौरान भारत ने इस बात को मजबूती से रखा कि यूक्रेन के आसपास पूर्व-पश्चिम ध्रुवीकरण को कैसे पार किया जाए और उत्तर-दक्षिण विकासात्मक विभाजन को कैसे पाटा जाए। विषम वैश्वीकरण, कोविड क्षति, यूक्रेन में संघर्ष, बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन और अब मध्य पूर्व में हिंसा के प्रभाव ने निश्चित रूप से दुनिया को कहीं अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित बना दिया है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उभरने के लिए फुर्तीली और 'मल्टी-वेक्टर' भारतीय कूटनीति की आवश्यकता है। सहमत मुद्दों पर अपने साझेदारों के साथ क्वाड तंत्र, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ब्रिक्स विस्तार और रचनात्मक मध्य पूर्व पहल में काम करना स्वाभाविक था

कुछ चुनौतियों के लिए दृढ़ संकल्प और नीतियों पर टिके रहने की आवश्यकता होती है। आतंकवाद को अवैध घोषित करवाना और उसका मुकाबला करना अभी भी ऐसा कार्य जिस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर दोहरे मानदंड को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीन के साथ भी रिश्ते तभी सामान्य हो सकते हैं, जब सीमावर्ती इलाकों में अमन-चैन बहाल हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरा सम्मान हो।

दुनिया अब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

शेष पृष्ठ 30 पर...

राष्ट्र-निर्माण का जनजातीय पथ

अर्जुन मुंडा

भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं वाला राष्ट्र है। हम स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अपने साहसी योद्धाओं की वीरता और बलिदान को याद करने में गर्व महसूस करते है। लेकिन देखा जाए तो जनजाति समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान और संघर्ष पर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जो जनजाति समाज और संस्कृति के प्रति अपने अटूट सम्मान और स्नेह के लिए जाने जाते हैं, ने आदिवासी समुदायों की वीरता को पहचाना।

भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ जंगलों के रक्षक नहीं थे, वह सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में खड़े रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अपने साथियों के साथ स्वयं का बलिदान दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में नामित किया है, जो देश भर में जनजातीय समुदाय को सम्मान देने के लिए एक समर्पित दिन है। इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस का तीसरा संस्करण मनाया जा रहा है।

इस दिन ने आदिवासी समुदायों के सह-अस्तित्व को पहचानने, सामाजिक समानता के उनके लंबे समय से पोषित सपने को मूर्त वास्तविकता में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। यह एक मार्मिक क्षण है जहां राष्ट्र जनजातीय आबादी की समृद्ध विरासत की सराहना करने और उसे अपनाने के लिए एक साथ आता है।

इसी तरह, राष्ट्र के विभिन्न कोनों में जनजाति समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश शासन का डटकर विरोध कर, एक अटूट दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया। आश्चर्य की बात है, बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली प्रतिरोध देश के जंगलों के बीचों-बीच जनजाति समाज से निकला था, जिनका जीवन और आजीविका जल, जंगल और जमीन के इर्द-गिर्द घूमती है क्योंकि वे सदैव प्रकृति के निकट रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में नामित किया है, जो देश भर में जनजातीय समुदाय को सम्मान देने के लिए एक समर्पित दिन है। इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस का तीसरा संस्करण मनाया जा रहा है

तिलका मांझी के नेतृत्व में पहाड़िया आंदोलन से लेकर बुधु भगत के नेतृत्व में लरका आंदोलन, सिद्धु मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल हूल आंदोलन, रानी गाइदिन्ल्यू के नेतृत्व में नागा आंदोलन, अल्लूरी सीतारमा राजू द्वारा संचालित रम्पा आंदोलन, गोविंद गुरु द्वारा आयोजित भगत आंदोलन तक— जनजाति समुदाय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की व्यापक छवि पेश कर एक अमिट छाप छोड़ी है।

बिरसा मुंडा, जिन्हें 'धरती आबा' के नाम से जाना जाता है, ने अपनी मातृभूमि के लिए एक भीषण लड़ाई लड़ी, जिससे अंग्रेजों को छोटा नागपुर टेनेंसी (सीएनटी) अधिनियम लागू करने के लिए प्रेरित किया। यह महत्वपूर्ण कानून भुइहर खूंट के बैनर तले पैतृक वन अधिकारों की रक्षा करता है— जल, जंगल और भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है।

भगवान बिरसा मुंडा के अथक संघर्ष को श्रद्धांजलि देने और आदिवासी क्षेत्रों में

ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करते हुए संसद ने वन अधिकार अधिनियम बनाया। बिरसा मुंडा का मुख्य लक्ष्य अपने स्थानीय समुदाय को बाहरी प्रभावों से बचाना था। इसलिए, पारंपरिक प्रणालियों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए पेसा (PESA) जैसे कानूनों की शुरुआत महत्वपूर्ण हो जाती है। पेसा को इन सदियों पुरानी प्रणालियों के साथ जुड़ना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों को सहजता से एकीकृत करना चाहिए। इसकी मूल अवधारणा अनुसूचित क्षेत्रों में एक पंचायत प्रणाली स्थापित करना है, जो सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक व्यवस्था को संरक्षित करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखती है।

जनजातीय समाज को पुनर्जीवित करने के कठिन कार्य को अपनाना भगवान बिरसा मुंडा के शाश्वत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा करके हम न केवल जनजाति संस्कृति की समृद्धि को संरक्षित करते हैं बल्कि गर्व के साथ उसका जश्न भी मनाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम इसे सामाजिक सद्भाव के साथ जोड़कर पुनर्स्थापन पर जोर देता है। किसी विशेष समूह को विशेष अधिकार प्रदान करने के बजाय यह अधिनियम संपूर्ण मानव समुदाय को समान हितधारकों के रूप में मान्यता देता है। विविध चुनौतियों का सामना करते हुए इन मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संबोधित करना सर्वोपरि है। सभी भारतीयों को प्रकृति की नाजुक परस्पर निर्भरता का संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। यह भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट दर्शन से मेल खाता है।

'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह हाशिए पर मौजूद समूहों की भलाई और सशक्तीकरण के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करता है। नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों के माध्यम से सरकार इन समुदायों के उत्थान और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास कर रही है।

संविधान अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी भलाई सुनिश्चित करने और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन अधिकार अधिनियम, पेसा और अन्य कानूनों ने जनजाति समुदायों के अधिकारों को मजबूत किया है, जिससे उन्हें अपने अद्वितीय जीवन शैली की रक्षा करने की शक्ति मिली है। ट्राइफेड और एनएसटीएफडीसी जैसे संस्थानों ने महत्वपूर्ण समर्थन और अवसर प्रदान किए हैं और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए जनजाति समुदायों की आर्थिक उन्नति को सक्षम बनाया है।

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जनजाति समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को राष्ट्र तेजी से स्वीकार कर रहा है। आइए, हम उनकी शानदार विरासत से प्रेरणा लें और एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों। ■

(लेखक केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं)

पृष्ठ 18 का शेष भाग...

में उभरी अति-एकाग्रता को ठीक कर रही है। परिणामस्वरूप लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेना एक प्रमुख भारतीय लक्ष्य बन गया है। इसी तरह डिजिटल डोमेन में विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नए तकनीकी उपकरणों को लेकर तैयारी कर रहा है। हम ऐसे पुनः वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं जो विविध, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और बाजार आधारित हो।

हरित विकास और सतत विकास पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रही दुनिया अब उस मूल्य को पहचान रही है जो भारत सामने लाता रहा है। हाल ही में इसने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक वैश्विक ग्रिड और खाद्य सुरक्षा के लिए बाजरा पर अधिक निर्भरता का प्रस्ताव करते हुए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की शुरुआत की है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और ऊर्जा दक्षता को मजबूत करने में भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। साथ ही, अपनी परंपराओं के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पहल हमारी दैनिक जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से दुनिया की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

विदेशों में भारत का बढ़ता प्रभाव घरेलू बदलावों के कारण भी है। महामारी के दौरान न केवल बड़े पैमाने पर सार्वजनिक-स्वास्थ्य व्यापक गईं; बल्कि सुविधाएं दी सुधार भी किए गए। बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना ने सामाजिक-आर्थिक लाभ और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बदल दिया है। इसी तरह, 2014 के बाद से शासन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिससे व्यवसाय करना आसान हो गया है और जीवनयापन में आसानी को बढ़ावा मिला है। इसे अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बुनियादी ढांचा पहल, बेहतर कौशल विकास और नवाचार एवं स्टार्ट-अप के प्रोत्साहन से बल मिला रहा है।

भारत की गहरी लोकतंत्रिक व्यवस्था ने प्रामाणिक और जमीनी राजनीति को भी पोषित किया है। संस्कृति और विरासत को महत्व देते हुए, प्रौद्योगिकी और आधुनिकता को अपनाना पिछले दशक की प्रगति में समान रूप से दिखाई देता है। आज का भारत कैशलेस भुगतान, 5जी नेटवर्क, चंद्रयान लैंडिंग और डिजिटल डिलीवरी कर रहा है। यह समान रूप से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और 'किसी को पीछे न छोड़ने' की राह पर चल रहा है। यह एक ऐसा समाज है जो अब अधिक आत्मविश्वासी, सक्षम और उत्तरदायी है। यह एक ऐसा राष्ट्र बन रहा है, जो भारत की परिकल्पना करता है। ■

(लेखक भारत के विदेश मंत्री हैं)

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में बहादुर जवानों के साथ मनाई दिवाली

जहां जवान तैनात हैं, वह जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 नवंबर को दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में बहादुर जवानों को संबोधित किया। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली के त्योहार और जवानों के साहस की प्रशंसा का मेल देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ज्ञान का एक क्षण है। उन्होंने भारत के सीमावर्ती इलाके पर स्थित देश के आखिरी गांव, जिसे अब पहला गांव माना गया है, में तैनात जवानों के साथ देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

अपने अनुभवों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उत्सव वहीं होता है जहां परिवार रहता है। उन्होंने सीमा की सुरक्षा के लिए त्योहार के दिन अपने परिवार से दूर रहने की स्थिति को कर्तव्यों के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने की भावना सुरक्षाकर्मियों के उद्देश्यों को सार्थकता प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा, "देश इसके लिए आपका आभारी और ऋणी है। इसीलिए हर घर में आपकी सुरक्षा के लिए एक 'दीया' जलाया जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "जहां जवान तैनात हैं वह जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। आप जहां भी हैं, मेरा त्योहार वहीं है। ऐसा शायद 30-35 वर्षों से चल रहा है।"

सशस्त्र बलों की बलिदान की परंपरा को नमन

प्रधानमंत्री ने जवानों और सशस्त्र बलों की बलिदान की परंपरा को नमन किया। उन्होंने कहा, "हमारे बहादुर जवानों ने खुद को सीमा पर सबसे मजबूत दीवार के रूप में साबित किया है।" श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हमारे बहादुर जवानों ने हार के जबड़े से जीत को छीनकर हमेशा नागरिकों का दिल जीता है।"

प्रधानमंत्री ने पिछली दिवाली के बाद से पिछले एक वर्ष के दौरान हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया और चंद्रयान लैंडिंग, आदित्य एल1, गगनयान से जुड़े परीक्षण, स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, तुमकुर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, वाइब्रेंट विलेज अभियान और खेलों से जुड़ी उपलब्धियों का उल्लेख किया।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, यह देश बेहतर भविष्य की दिशा में प्रयास करता रहेगा। उन्होंने भारत के विकास का श्रेय सशस्त्र बलों की शक्ति, संकल्प और बलिदान को दिया।

श्री मोदी ने उच्च-तकनीक पर आधारित प्रौद्योगिकी एवं सीडीएस जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों के समन्वय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना लगातार और अधिक आधुनिक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अब निकट भविष्य में जरूरत के समय दूसरे देशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा।

श्री मोदी ने कहा, "आज स्वदेशी संसाधन और उच्च श्रेणी का सीमा संबंधी बुनियादी ढांचा भी हमारी ताकत बन रहे हैं और मुझे ख़ुशी है कि नारीशक्ति भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है।" उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान 500 महिला अधिकारियों की कमीशनिंग, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलटों और युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों की तैनाती का उल्लेख किया।

सशस्त्र बलों की जरूरतों का ख्याल रखने के महत्व के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने अत्यधिक तापमान के लिए उपयुक्त कपड़े, जवानों की बेहतरी एवं सुरक्षा के लिए ड्रोन और 'वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत 90 हजार करोड़ रुपये के भुगतान का उल्लेख किया।

एक दोहे के साथ अपने संबोधन का समापन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों का हर कदम इतिहास की दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सशस्त्र बल इसी दृढ़ संकल्प के साथ भारत माता की सेवा करते रहेंगे। श्री मोदी ने कहा, "आपके सहयोग से देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। हम मिलकर देश के हर संकल्प को पूरा करेंगे।" ■

दूसरा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन

हमारे हित समान हैं, हमारी प्राथमिकताएं समान हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 नवंबर को दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉयस पहली बार मिल रही है और ये हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि हम 100 से ज्यादा अलग-अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान हैं, हमारी प्राथमिकताएं समान हैं। श्री मोदी ने कहा कि मैं वो ऐतिहासिक क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से अफ़्रीकी संघ को नई दिल्ली समिट में जी-20 की स्थायी सदस्यता मिली।

उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि नई टेक्नॉलॉजी, नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज Artificial Intelligence (कृत्रिम मेधा) AI के युग में टेक्नॉलॉजी को जिम्मेदार तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है।

श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक समृद्धि के लिए 'सबका साथ और सबका विकास' जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है।

उन्होंने कहा कि हमने संयम के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के संघर्ष में नागरिकों की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बातकर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश बृहत्तर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। ■

वर्चुअल जी-20 शिखर सम्मेलन

आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 नवंबर को वर्चुअल जी-20 शिखर सम्मेलन में अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अविश्वास और चुनौतियों से भरी आज की दुनिया में ये आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक साल में हमने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' में विश्वास जताया है और विवादों से हटकर एकता और सहयोग का परिचय दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले महीनों में नयी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति हम सबके लिए चिंता का विषय है। आज हमारा एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के विश्व को आगे बढ़ते हुए ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। ग्लोबल साउथ के देश ऐसी अनेक कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं जिनके लिए वे ज़िम्मेदार नहीं है। इस संदर्भ में समय की मांग है कि हम विकास एजेंडा को अपना पूर्ण समर्थन दें।

श्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी बनाने का निर्णय लिया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि यह रिपॉजिटरी तैयार हो गई है। इसमें 16 देशों के 50 से भी ज्यादा DPI जुड़ गए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों मे DPI इम्प्लिमेन्ट करने के लिए मैं सोशल इम्पैक्ट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। भारत की ओर से मैं इसमें 25 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक राशि भी जोड़ने की घोषणा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पहल से जुड़ेंगे। ■

आपातकाल के सेनानी नरेन्द्र मोदी

संपादित एवं संकलितः ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन एवं मोदी स्टोरी

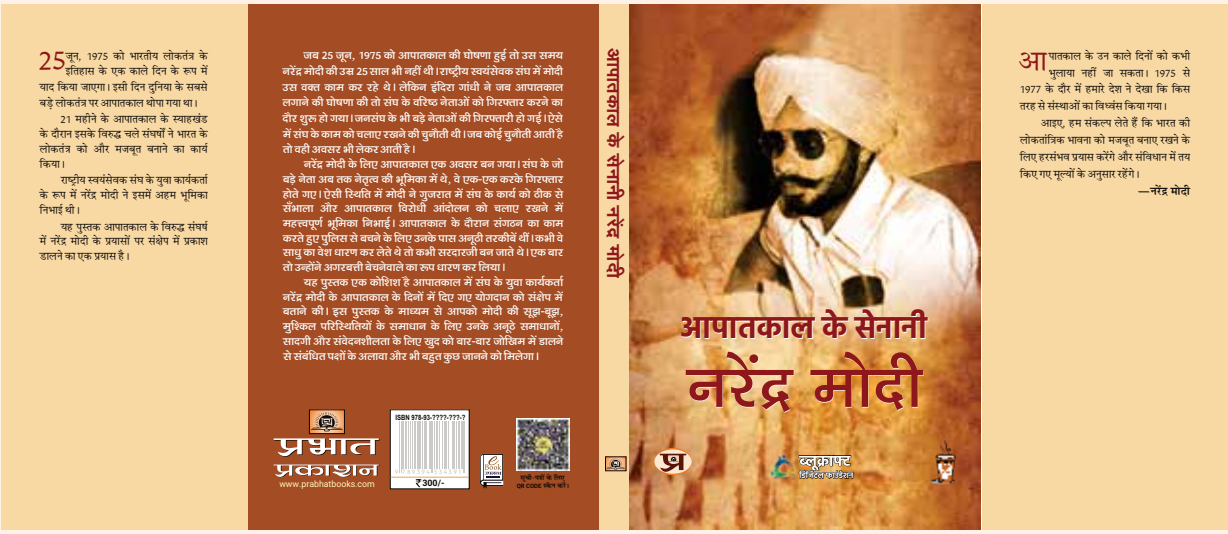

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आपातकाल थोप दिया था।

गुजरात से आरंभ नवनिर्माण आंदोलन और बिहार से शुरू हुए छात्र आंदोलन ने पूरे देश में इंदिरा गांधी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का कार्य किया। जब इलाहबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करने का फैसला सुनाया, तो पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया।

आपातकाल लागू होते ही देश भर में सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण (जे.पी.) आपातकाल लगने से पहले ही इंदिरा गांधी के कुशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आपातकाल लगते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के अन्य बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री नरेन्द्र मोदी उस समय 25 वर्ष के भी नहीं थे। श्री मोदी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद संघ का कार्य जारी रखने की चुनौती थी। ये चुनौती गुजरात में भी थी।

ऐसे में श्री मोदी ने गुजरात में आपातकाल विरोधी आंदोलन को निरंतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। श्री नरेन्द्र मोदी, जो संघ के स्वयंसेवक थे, ने भी इस अवधि के दौरान अपने संगठनात्मक कौशल का विकास किया।

जे.पी. तथा नानाजी देशमुख जैसे अन्य लोगों के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर एक लोक संघर्ष समिति का गठन किया गया। गुजरात में इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी श्री नरेन्द्र मोदी को दी गयी। साहित्य का प्रकाशन, संगठनात्मक कार्य करना, आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष और सत्याग्रह आदि कार्य इसी समिति की देखरेख में किये गये। इसमें श्री नरेन्द्र मोदी की अहम भूमिका रही।

श्री मोदी ने संघ स्वयंसेवकों की मदद से आपातकाल विरोधी साहित्य और पत्रिकाओं के लिए सामग्री एकत्र करने, प्रकाशित करने और वितरित करने की जिम्मेदारी संभाली। गुजरात में प्रकाशित साहित्य को प्रदेश के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी ले जाना था।

आपातकाल के दौरान संगठनात्मक कार्य करते हुए पुलिस से बचने के लिए श्री मोदी ने अनोखे तरीकों को अपनाया। कभी वे साधु बनकर घूमते रहे, कभी वह सरदारजी बन जाते थे।

आपातकाल के दौरान श्री मोदी ने उन कार्यकर्ताओं के परिवारों की भी सुध ली, जो गिरफ्तार किये गये थे। देश के शीर्ष नेताओं के गुजरात आने पर उनकी यात्रा की व्यवस्था करने और उनकी बैठकें आयोजित करने की जिम्मेदारी भी उन पर थी।

यह पुस्तक 'आपातकाल के सेनानी नरेन्द्र मोदी' आपातकाल के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी के योगदान को एक साथ रखने का एक प्रयास है। यह किताब अब अमेजन, फ्लिपकार्ट और प्रभात बुक्स पर उपलब्ध है। ■

प्रकाशकः प्रभात प्रकाशन, पृष्ठः 134, मूल्यः 250/-

'भारत में बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही'

14 नवंबर, 2023 को जारी एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और देश का श्रम बाजार संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।' इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सभी क्षेत्रों में स्व-उद्यमिता के साथ गहन संरचनात्मक बदलावों को देखा गया है और इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा प्राप्ति प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में उभर रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और कोविड महामारी के बाद निचले पायदान पर मौजूद लोगों के लिए पीएम-स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता पर सरकार का जोर 'ऐसे पारिवारिक उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण व्यवस्था कर, भारत में श्रम बाजारों में एक संरचनात्मक बदलाव प्रदान कर रही है।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी श्रेणियों में आय में वृद्धि हुई है, राज्य की अतिरिक्त योजनाओं के साथ 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन, पीएमएवाई और आयुष्मान भारत के माध्यम से सरकार भोजन, आश्रय और चिकित्सा जरूरतों जैसी प्राथमिक निर्वाह आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है, जिससे लोग आय और पारिवारिक उद्यमों में संतुलन बनाने में सक्षम हुए है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

लेप्चा (हिमाचल प्रदेश) में 12 नवंबर, 2023 को जवानों के साथ दिवाली मनाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सागवाड़ा (राजस्थान) में एक जनसभा 22 नवंबर, 2023 को जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

रांची (झारखंड) में 14 नवंबर, 2023 को जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

रांची (झारखंड) में 15 नवंबर, 2023 को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 नवंबर, 2023 को दूसरे वॉयस ऑफ द् ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

22 नवंबर, 2023 को वर्चुअल जी-20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 29 नवंबर, 2023
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

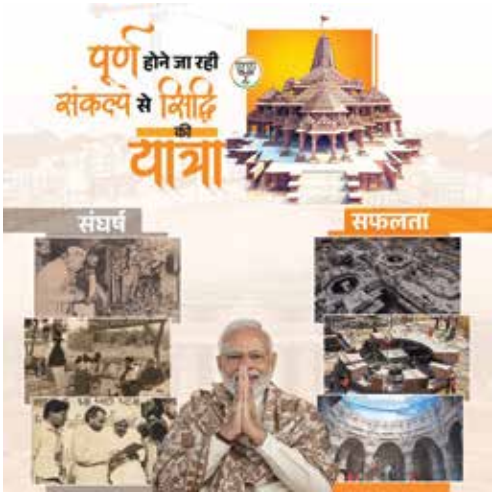

छायाकार: अजय कुमार सिंह